सैन्य सन्देश Sainya Sandesh

युगाब्द 5127 आषाढ–श्रावण, 2082 जुलाई, 25

शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से सफल वापसी

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद् का मुखपत्र

लखनऊ (उ.प्र.)

बुलन्दशहर (उ.प्र.)

जोधपुर (राजस्थान)

हरदोई (उ.प्र.)

कानपुर (उ.प्र.)

पुणे (महाराष्ट्र)

रीवां (म.प्र.)

इंदौर (म.प्र.)

जबलपुर (म.प्र.)

RNI Reg No.UPBIL/2002/9228

27. December 2023 Postal Reg. SSP/LW/NewsPaper-01-2024-2026
Despatched from- Lko RMS Non TD.
Dates of Despatch- 5,22 & 28

कोटद्वार (उत्तराखण्ड)

कारगिल यात्रा जुलाई 2025

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

के सदस्य बनें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें

मो. : 8317082620, 8004402890
Website: www.sainyasandesh.co.in
E-mail : sainyasandesh@gmail.com, info@sainyasandesh.co.in

सेवा में

अ.भा. पूर्व सैनिक सेवा परिषद् के लिए अतिथि मुद्रक एवं प्रकाशक कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी ने हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा, हजरतगंज, लखनऊ से मुद्रित कराकर, 3 नीवन मार्केट, बी.एन.रोड, कैसरबाग, लखनऊ से प्रकाशित किया।

सैन्य-सन्देश (मासिक)

राष्ट्रहित, समाजहित, सैनिक-हित को समर्पित पत्रिका

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद का मुख-पत्र

वर्ष–26 | आषाढ़–श्रावण 2082 | जुलाई, 2025

संरक्षक मण्डल

ले.ज.वी.के.चतुर्वेदी PVSM, AVSM,SM

ए.वी.एम. एच.पी. सिंह, VrC, VSM

प्रबन्धक मण्डल

ब्रिगेडियर डी एस त्रिपाठी

ब्रिगेडियर गोविन्दजी मिश्र VSM,PPM

सम्पादकीय सलाहकार

ले.जन. दुष्यन्त सिंह PVSM,AVSM

मुख्य सम्पादक

कर्नल लक्ष्मीकान्त तिवारी

सह-सम्पादक

सू.मे. जे.बी.एस. चौहान

प्रबन्धन विपणन एवं प्रचार-प्रसार

ले. कर्नल वीरेन्द्र सिंह तोमर

श्री प्रमोद कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष

सीपीओ घनश्याम प्रसाद केसरी

सीपीओ डीडी पाण्डेय

(सभी पद अवैतनिक)

मुद्रित :

हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा प्रा0 लि0

प्रस्तुति

हिन्दी अनुभाग

1. संपादक की कलम से भारत की चुनौतियां और... 2
2. भविष्य की आधारशिला रखने वाला एक्सिओम मिशन 3–4
3. ट्रंप से अब और सावधान रहना हो जाए भारत 5–6
4. दम तोड़ते दिख रहे माओवादी 7–8
5. राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता 9–10
6. और बढ़ी वायु सैन्य शक्ति की महत्ता 11–12
7. आनंद का विज्ञान योग 13–14
8. भारतीय राष्ट्रवाद में स्वामी विवेकानन्द का योगदान 15–17
9. चीन पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़ 18–19
10. कारगिल विजय यात्रा-भारत के वीर सपूतों... 20–22

English Section

1. Why do nations acquire Nukes: decoding... 23-24
2. Bolstering borders, providing cover 25-27
3. New Details Emerge on India's Devastating... 28-29
4. China, Pakistan and Bangladesh from... 30-31
6. Welfare 32-34
9. गतिविधियां 35-36

सम्पादकीय कार्यालय : 3, नवीन मार्केट, बी.एन. रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

मो. : 8004402890, 8317082620, 9651217002

Website: www.sainyasandesh.co.in

E-mail : sainyasandesh@gmail.com

The Publishers and Authors reserve the rights in regard to the contents of 'Sainya Sandesh'. The images and certain content used herein are from public domain, belongs to their respective owners and the same is being used herein for awareness and educational purposes only. The Magazine is non commercial, non profitable and intended to create awareness amongst soldiers community.

भारत की चुनौतियाँ और हमारे कर्त्तव्य

भारत, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है जो आज अनेक समकालीन चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे प्रमुख चुनौती है– बढ़ती जनसंख्या और उससे उत्पन्न बेरोजगारी, जिससे विशेषकर युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। शिक्षा और कौशल विकास की कमी से युवाओं की प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता और महंगाई भी आम जनता के जीवन को कठिन बना रही है। भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव, आतंकवाद और साइबर युद्ध की संभावनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। साथ ही, आंतरिक स्तर पर सांप्रदायिकता, जातिवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण सामाजिक समरसता को कमजोर कर रहे हैं। तकनीकी युग में डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग, फर्जी खबरें और साइबर अपराध लोकतंत्र की नींव को प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरणीय संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, जल संकट और वायु प्रदूषण भी भविष्य को चुनौती दे रहे हैं।

इन सबका समाधान एक सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व, सजग नागरिक भागीदारी तथा राष्ट्रीय एकता में निहित है। भारत को अपने सांस्कृतिक मूल्यों, वैज्ञानिक सोच और युवा शक्ति के बल पर इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करें। हमें अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर योगदान करना चाहिए, चाहे वह स्वच्छता, शिक्षा, या सामाजिक जागरूकता के माध्यम से हो। सरकार, समाज और नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक विकसित और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। एकजुटता और सहयोग से ही हम इस संकट को पार कर सकेंगे।

कर्नल लक्ष्मी कान्त तिवारी
मुख्य संपादक

हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता है कि हवा चल रही होती है, बल्कि हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है, जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को यूंही न्योछावर कर देता है!

Our tricolor does not fly because the wind is moving, but our tricolor flutters with the last breath of the young man who sacrificed his life to protect our tricolor!

भविष्य की आधारशिला रखने वाला एक्सिओम मिशन

सृजन पाल सिंह

भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन–आइएसएस में दाखिल होकर एक नया इतिहास रचा। वह एक्सिओम 4 मिशन का हिस्सा हैं। यह मिशन नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का समन्वित प्रयास है। इस मिशन के दौरान 60 वैज्ञानिक परीक्षण किए गये। इन परीक्षणों में 31 देशों का योगदान रहा, जिनमें सात परीक्षणों में इसरो की सक्रिय भूमिका है। ये परीक्षण माइक्रोबायोलाजी, बायोटेक्नोलाजी, पदार्थ विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे विविध विषयों से जुड़े हैं। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषकों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जाने, प्रवास या अंतरिक्ष में प्रयोग–परीक्षण करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें उस भविष्य की कुंजी निहित है, जिसमें अंतरिक्ष केवल अन्वेषण का ही एक केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे के रूप में भी स्थापित होगा।

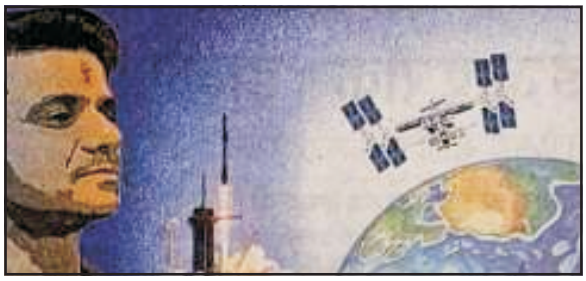

यह स्पष्ट है कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष भूराजनीति, वैश्विक शक्ति समीकरण और आर्थिक वृद्धि को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। चाहे उपग्रह संचार से लेकर रक्षा प्रणालियों का मामला हो या संसाधन उत्खनन से अंतरिक्ष पर्यटन का विषय, उनमें देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं ही यह निर्धारित करेंगी कि कौन देश इसमें बढ़त बनाएगा और कौन अनुसरण करेगा। अंतरिक्ष में नियंत्रण का अर्थ है संचार पर नियंत्रण ? यह स्थिति युद्ध और टकराव में बहुत उपयोगी साबित होती है। सैटेलाइट नेटवर्क की महत्ता तो सैन्य संचार से लेकर रियल टाइम नेविगेशन और जलवायु निगरानी के मोर्चे पर पहले ही सिद्ध हो चुकी है। रूस–यूक्रेन युद्ध इसका उदाहरण है। जब रूस ने यूक्रेन के संचार ढांचे को तबाह कर दिया तब एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सुविधा ही यूक्रेन के काम आई।

आधुनिक समर नीति में भी अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है। सशक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देशों को स्वाभाविक रूप से सामरिक बढ़त मिलती है। ईरान–इजरायल के हालिया युद्ध में भी इसका प्रमाण दिखा, जहां ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल के एयरो–3 डिफेंस सिस्टम ने पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर ही निष्प्रभावी कर दिया। यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कैसे आधुनिक समर नीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बीते दिनों भारत के आपरेशन सिंदूर में भी सैटेलाइट कैमरों की उपयोगिता दिखी, जिन्होंने लक्ष्यों को चिह्नित करने और नुकसान के आकलन में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए

स्पेस फोर्स नाम से एक अलग सैन्य इकाई का गठन किया है। भारत भी इस संकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ने जा रहा है।

आर्थिक मोर्चे पर भी अंतरिक्ष नया अखाड़ा बन रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन अब कोई कपोल कल्पना नहीं। कुछ कंपनियों–संगठनों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसरो भी इस दिशा में काम कर रहा है और उसकी 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की योजना है। 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन कारोबार के 85,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

चूंकि भारत की पहचान विश्वसनीय और किफायती प्रक्षेपण क्षमताओं वाले देश की है. इसलिए यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस बाजार में उसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होने वाला है। विस्तार ले रही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वही देश बाजी मारने में सफल हो सकते हैं, जो मनुष्यों से लेकर मशीनों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होंगे। ऊंचे दांव वाली इस होड़ में भारत बिल्कुल सटीक मौके पर कदम रखकर महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा में एक्सिओम–4 मिशन एक मील का पत्थर है। सीधे तौर पर इसका सरोकार भारत के गगनयान कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत स्वदेश निर्मित यान के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की योजना है। यह 2027 तक संभव हो सकता है। हालांकि भारत के इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन–बीएएस के रूप में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। यह केंद्र अत्याधुनिक शोध अनुसंधान, नवाचार एवं लंबी अवधि वाले मिशन के लिए एक मंच की भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में स्थायी मानवीय उपस्थिति वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। एक्सिओम–4 मिशन के दौरान लाइफ साइंस, कक्षीय परिचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मोर्चे पर सीखे जाने वाले सबक बीएएस के डिजाइन और संचालन ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अंतरिक्ष में मूल्यवान संसाधनों का भंडार भी छिपा है। इस संदर्भ में मंगल (एस्टेरॉयड) बेल्ट सर्वाधिक संपन्न है। इनमें प्लेटिनम, सोना, कोबाल्ट, (लीथियम जैसे वैसे दुर्लभ संसाधन हैं, जो बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक जैसी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी पर सिकुड़ते संसाधनों को देखते हुए भविष्य की आर्थिकी में अंतरिक्ष खनन का महत्व बढ़ेगा। समझ लीजिए कि संपूर्ण विश्व का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी करीब 100 ट्रिलियन (लाख करोड़ डालर है। दुनिया के उत्पादन से करीब 8,000 गुना अधिक है। यानी वहां मौजूद खनिजों का मूल्य इतना अधिक है कि पूरी दुनिया अगली 80 शताब्दियों तक कमाई के जरिये ही उसकी बराबरी कर पाएगी। जो देश इन इलाकों में सबसे पहले पहुंचकर उसके कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, वही भविष्य के उद्योगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के चक्र को नियंत्रित कर सकेंगे। वे कीमतों के निर्धारण, नए उद्यमों की स्थापना और वैश्विक बाजारों को आकार देंगे। यही वजह है कि अंतरिक्ष में पैठ भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं और महारत से भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी और प्रशिक्षण के जरिये अंतरिक्ष में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व कर सकता है। यह रणनीति कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण को भी कहीं अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत बनाएगी।

यह बड़े ही हर्ष की बात है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बाकी अंतरिक्ष यात्री 'ड्रैगन ग्रेस' अंतरिक्ष यान से सकुशल कैलीफोर्निया के प्रशांत महासागर में 15 जुलाई को सकुशल वापस लौटे हैं। एक्सिओम 4 मिशन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु की सकुशल वापसी पर खुशी जाहिर की है।

ट्रंप से अब और सावधान हो जाए भारत

दिव्य कुमार सोती

कुछ दिनों के भीषण युद्ध के बाद इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो गया। कहना मुश्किल है कि यह संघर्ष विराम कितने समय तक टिकेगा ? ईरान पर हमला बोलते समय इजरायल ने यह कहा था कि उसका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है। उसे कुछ आरंभिक सफलता भी हासिल हुई। उसके अचानक हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु विज्ञानी मारे गए। शुरुआती सफलता के बीच इजरायल ने कहना शुरू कर दिया कि हमले के पीछे उसके उद्देश्य बड़े हैं और एक उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी है। ईरान की सत्ता उन कट्टर मजहबी नेताओं के कब्जे में है, जो हमास – हिजबुल्ला का साथ देते हैं। इजरायल के समर्थन में अमेरिका के कई ताकतवर नवरूढ़िवादी सांसदों की आवाज भी उठने लगी। शुरुआत में अमेरिका इस लड़ाई में कूदने से हिचक रहा था, पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से घिरे इजरायल की मदद के लिए आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी वायु सेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के आदेश देने ही पड़े। इसके बावजूद ईरानी परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह ध्वस्त होने को लेकर संदेह है। वैसे भी ईरान की मिसाइल क्षमता आशा से कहीं अधिक निकली युद्ध लंबा खिंचने पर इजराइल में कहीं अधिक बर्बादी हो सकती थी। इसी कारण ट्रंप ने आनन–फानन युद्ध विराम का एलान भी कर दिया और वह भी अपने व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति के बिना, क्योंकि न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो पाया और न ही वहां सत्ता परिवर्तन के कोई आसार के दिख रहे। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि इजरायल और ट्रंप के मागा (मेक अमेरिकी ग्रेट अगेन) खेमे ने यह योजना सदा के लिए छोड़ दी है। सही मौका न देखकर इसे फिर से क्रियान्वित करने का प्रयास होगा।

वैसे तो अमेरिका को फिर से महान बनाने के अभियान में लगा ट्रंप प्रशासन ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए किसी जमीनी युद्ध में नहीं उलझना चाहता, परंतु उसके इरादों को देखते हुए भारत को सतर्क होना होगा। भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी इस युद्ध के निहितार्थ समझने की आवश्यकता है। इजरायल–ईरान युद्ध के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप की ओर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आवभगत का एक गहरा अर्थ है। जब मुनीर व्हाइट हाउस में थे, लगभग उसी समय अमेरिकी मदद से सत्तासीन बांग्लादेश की भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी

वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मिल रहे थे। दरअसल ट्रंप की मागा योजना के अंतर्गत अमेरिका का नए सिरे से जो उद्योगीकरण प्रस्तावित है, वह बिना चीन और रूस के पर कतरे और भारत को तंग किए बिना संभव नहीं है। इस योजना को सिरे चढ़ाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भूमंडलीकरण के नाम पर अमेरिका ने ही अधिक मुनाफा कमाने के फेर में अपनी कंपनियों को चीन, वियतनाम जैसे देशों में स्थापित कराया। अब जब तक इन देशों में अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पादन

के मोर्चे पर चुनौतियां नहीं दिखतीं, तब तक उनकी स्वदेश वापसी मुश्किल है। फिर भी अपनी योजना को लेकर अमेरिकी नवरूढ़िवादियों और ट्रंप के कथित युद्धविरोधी मागा खेमे में एक राय है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो तरीके चुने गए हैं।

पहला तरीका है ट्रेड और टैरिफ नीति के जरिये रूस, चीन के साथ–साथ भारत का भी आर्थिक संकट बढ़ाना। दूसरा तरीका है कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों का अपने हित में इस्तेमाल करना। ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर लगाए गए भारी टैरिफ के चलते चीन का अमेरिका को निर्यात काफी घटा है। यदि यह सिलसिला लंबे समय तक चला और चीन ने अपने निर्यात के लिए नए बाजार नहीं तलाशे तो वहां बड़ा औद्योगिक और सामाजिक संकट खड़ा हो सकता है।

भारत चीन के विरुद्ध एक तरह से अमेरिका का सामरिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप मात्र इतने से संतुष्ट नहीं। उन्हें भारत के रूप में एक लोकतांत्रिक मित्र राष्ट्र नहीं, बल्कि उनके हिसाब से चलने वाला देश चाहिए। भारत के अमेरिका के बताए रास्ते पर चलने से साफ इन्कार करने के बाद अब यह अमेरिका के एजेंडे में नहीं दिखता कि उसकी मदद से भारत चीन जैसी आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा हो। यह अच्छा हुआ कि भारत ने साफ कर दिया कि उसे अमेरिका से व्यापार समझौते की जल्दी नहीं।

ट्रंप ने हाल में यह भी कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और वह अपने मसले खुद देख लेगा। ध्यान रहे एक अमेरिकी सीनटेर रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की वकालत कर चुके हैं। पाकिस्तान को शह देते ट्रंप भी भारत– पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे को भी जब तब व्यापार से जोड़ते रहते हैं। इसके पीछे उनका भारत के लिए यही संदेश है कि अगर टैरिफ जैसे मुद्दे पर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे पाकिस्तान के मोर्चे पर और दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। यदि बांग्लादेश में भी अमेरिका लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है तो भारत को परेशान करने के लिए हीं। इन परिस्थितियों में रूसी विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तावित रूस, चीन और भारत का त्रिकोण अब प्रासंगिक लगता है। चीन भी अब इसे लेकर सजग हो रहा है। भारत और चीन के रिश्तों में बर्फ पिघलती देखी जा सकती है। हाल में शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद आए चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में उल्लेख हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी न होकर साझेदार हैं। जहां अमेरिकी टैरिफ के चलते चीन को एक बड़े बाजार की आवश्यकता है, वहीं भारत को त्वरित औद्योगिक विकास के लिए सस्ते कलपुर्जों की। दोनों देश एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इसके बावजूद भारत को अपने सुरक्षा हितों के मामले में चीन को लेकर निरंतर सजग रहते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर पूर्व में चीन से बार–बार धोखा मिल चुका है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन के साथ आर्थिक साझेदारी भारत के औद्योगिक विकास में सहायक हो और वह चीन पर निर्भरता का कारण न बने।

सैन्य संदेश के सदस्य बनें

पत्रिका 'सैन्य संदेश' का सदस्य बनें। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हर पदाधिकारी को पत्रिका का आजीवन सदस्य (Life Time Member) बनना अपेक्षित है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रू0 300/– और आजीवन सदस्यता शुल्क रू0 2500/– है। वार्षिक सदस्यों को एक वर्ष बाद पुनः सदस्यता नवीनीकरण अनिवार्य है जिसके लिये प्रति वर्ष रू0 300/– देय है। सदस्यता शुल्क आनलाइन पेयमेंट (Editor Sainya Sandesh A/c No. 0293000109102061 Punjab National Bank, IFS Code PUNB0029300) पर देय है। ऑनलाइन पेयमेंट का स्क्रीन शॉट सैन्य संदेश नेशनल whatsapp ग्रुप में या सम्पादक/सहसम्पादक/ कोषाध्यक्ष के फोन पर जो पत्रिका में सबसे पीछे के पृष्ठ पर अंकित है, भेजें। साथ में सब्सक्राइबर सदस्य का पोस्टल एड्रेस पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर के साथ अवश्य भेजें।

दम तोड़ते दिख रहे माओवादी

उमेश चतुर्वेदी

हर शासक का असल मूल्यांकन इतिहास करता है। मोदी सरकार का भी करेगा। लोकतांत्रिक भारत की सत्ता के केंद्र अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बने हुए हैं, तो इसकी वजह उनकी कई उपलब्धियां भी हैं। मोदी के शासन की सफलताओं में से एक है देश से वामपंथी उग्रवाद का लगभग सफाया। मोदी सरकार माओवादी आतंक के खात्मे के लक्ष्य पर शुरू से ही काम करती रही है, लेकिन अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद इसमें तेजी आई है। इसका असर अब दिखने लगा है। माओवादियों के पांव उखड़ रहे हैं, वे सरेंडर करके सामाजिक मुख्यधारा में लौट रहे हैं, लेकिन सियासी जुबान में माओवाद की गूंज सुनाई देती रहती है। पहले नक्सली कहे जाने वाले माओवादी भी अभी पूरी तौर पर पस्त नहीं हुए हैं। उनसे वैचारिक स्तर पर भी लड़ने की जरूरत है।

1925 में विरोधी वैचारिक छोर पर खड़े दो संगठनों का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद के ध्येय के साथ विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ तो लगभग तीन माह बाद दिसंबर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सौ वर्षों की यात्रा में कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर होता गया, जबकि संगठन और विचार के स्तर पर संघ विराट वृक्ष बन चुका है। आजादी के बाद ही आंध्र प्रदेश में हथियारबंद कथित कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हो गई थी, लेकिन इसे गति 1970 के दशक की शुरुआत में बंगाल के नक्सलबाड़ी से मिली। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग का कहना था कि सत्ता बारूद से निकलती है। नक्सल आंदोलन ने दो तरह से अपना प्रभाव बढ़ाया। शैक्षिक संस्थानों और वैचारिक प्रतिष्ठानों में इस वैचारिकी ने बौद्धिक जड़ें जमाईं तो दूसरी तरफ खेतों और जंगलों में खूनी क्रांति का सपना पूरा करने के लिए नौजवान हाथों ने हथियार थाम लिए। धीरे–धीरे वैचारिक प्रतिष्ठानों में इस विचार का वैचारिक प्रभाव तो बढ़ा ही, जंगलों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों में हथियारबंद संगठनों का असर बढ़ा। हथियारबंद आंदोलन की पहले जो नक्सलवादी पहचान थी, उसे माओवादी के रूप में जाना जाने लगा। जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में हथियारबंद आंदोलन जहां खूंखार होता गया।

वहीं उसे वैचारिक कवच वैचारिक प्रतिष्ठानों के बौद्धिकों से मिलने लगा। वैचारिक प्रतिष्ठानों

में माओवाद समर्थकं लोग तत्कालीन सत्ता का विरोध करते हुए भी सत्ता प्रतिष्ठानों के आदरणीय बने रहे, जबकि हथियारबंद दस्तों ने सत्ता के खिलाफ खूनी संघर्ष जारी रखा। एक दौर में छत्तीसगढ़, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर उनका असर हो गया।

मोदी सरकार के सत्ता संभालते वक्त देश के लगभग एक चौथाई जिलों में लाल आतंक कायम था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार अब महज 18 जिलों में ही माओवाद का प्रभाव है। माओवाद कितना दुस्साहसी है, इसका अंदाजा दो घटनाओं से लगाया जा सकता है। माओवादियों ने 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को विस्फोट से उड़ाकर तत्कालीन सत्ता को चुनौती दे डाली थी। इसके तीन साल बाद छत्तीसगढ़ की ही दरभा घाटी में माओवादियों ने घात लगाकर राज्य कांग्रेस के करीब–करीब पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया था।

ताड़मेटला की घटना से क्रुद्ध मनमोहन सरकार ने जंगलों में छिपे माओवादियों पर हवाई कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, पर शहरों के वैचारिक प्रतिष्ठानों में काबिज उसके वैचारिक दस्तों के प्रबल विरोध के चलते उसे पीछे हटना पड़ा था। चाहे हथियारबंद माओवादी दस्ते हों या शहरी प्रतिष्ठानों की माओवाद समर्थक वैचारिकी, दोनों के निशाने पर संघ और भाजपा रहे हैं।

2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा ने जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया, उसमें माओवादी हिंसा को खत्म करने का भी लक्ष्य तय किया गया था। माओवादी हिंसा के चलते आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति धीमी पड़ी। इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में हथियारबंद दस्तों का प्रतिरोध बड़ी बाधा रहा। माओवादी अक्सर स्कूलों, पंचायत भवनों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों आदि को निशाना बनाते रहे हैं। मोदी सरकार ने माओवाद के खात्मे के लिए दो मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। हथियार उठाने वालों के लिए जहां गोली का जवाब गोली से देने की नीति अपनाई, वहीं माओवादियों के सरेंडर और उनके सामाजिक पुनरुत्थान पर जोर दिया। पिछड़े इलाकों में सड़कें और रेलवे लाइन पहुंचाई गईं। मोदी सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूल बनाने और विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया। सरकारी नीतियों को लागू करने और माओवादी हथियारबंद दस्तों के खिलाफ कार्रवाई में हाल में काफी तेजी आई है।

एक तरफ जहां माओवादी हिंसा पर लगाम लग रही है, वहीं सियासी वैचारिकी में माओवाद का विस्तार होता दिख रहा है। राहुल गांधी एक बार यह कह चुके हैं कि वह भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यही भाषा माओवादियों की भी है। जिस कांग्रेस के छत्तीसगढ़ नेतृत्व का माओवाद ने खात्मा कर दिया था, उसी कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नक्सल आंदोलन को सामाजिक आंदोलन बता रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की वापसी कहीं दिख नहीं रही, लेकिन कुछ मामलों में उनकी और कांग्रेस की भाषा एक सी रहती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता

प्रकाश सिंह

बांग्लादेशियों की भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ से पैदा समस्याओं के प्रति भारत में दशकों तक सुस्ती दिखाए जाने के बाद अब कुछ जागृति दिखाई दे रही है। कई राज्यों में उनकी धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे जाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले छह महीनों के दौरान करीब 800 बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। असम में विशेष तौर से बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। असम ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित नहीं कर देंगे, तब तक किसी को आधार पहचान पत्र नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के समाचार आए हैं, फिर भी हमें यह समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है, वह बांग्लादेशियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए शून्य है। वैसे तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग बराबर भारत में घुसपैठ करते रहे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सोचा गया कि अब घुसपैठ कम हो जाएगी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ नया देश बनने के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा और उनकी स्थिति खस्ताहाल बनी रही। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान, दोनों ही अलग–अलग कारणों से भारत आते रहे। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार 1951 और 1961 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति 'गायब' हो गए। इसी प्रकार 1961 से 1974 के बीच 15 लाख व्यक्तियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये व्यक्ति हवा में नहीं उड़ गए। ये सब भारत चले आए। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने लेबेस्राम की भी एक थ्योरी चलाई। इसके अनुसार अधिक जनसंख्या के क्षेत्र से कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों का प्रवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बांग्लादेशियों का भारत जाना स्वाभाविक हैं। दुर्भाग्य से भारत की किसी भी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स बनाई थीं। इनमें से एक टास्क फोर्स बार्डर मैनेजमेंट यानी सीमा प्रबंधन से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष माधव गोडबोले थे, जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अगस्त 2000 में भारत सरकार, को सौंपी रिपोर्ट में खेद प्रकट किया कि देश में हर पार्टी में इस समस्या के प्रति उदासीनता थी और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने साफ लिखा कि इस समस्या को लेकर सारी जानकारी और उससे निपटने के पर्याप्त संसाधन थे, पर राजनीतिक वर्ग में समस्या से निपटने के तरीकों में कोई सहमति न होने के कारण निष्क्रियता रही। टास्क फोर्स के आकलन के अनुसार हर महीने करीब 25 हजार यानी प्रतिवर्ष तीन लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आते रहे और भारत में उनकी कुल संख्या उस समय तक करीब 1.5 करोड़ थी। बांग्लादेश–भारत सीमा पर जैसे–जैसे फेंसिंग लगती गई, घुसपैठियों की संख्या में कमी होती गई। फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भारत में इस समय कम से कम दो करोड़ होगी। 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है वह देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में एक फैसले में कहा कि असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण आंतरिक उथल–पुथल और विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस परिस्थिति में

भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि असम की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 355. के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाई करे। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट, मंत्रियों के समूह की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की नींद नहीं खुली और स्थिति जस की तस बनी रही। क्या यूपीए सरकार, क्या एनडीए सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और शेख हसीना वहां से बचकर भारत में निर्वासित रूप में रह रही हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है, जो भारत विरोधी है, तब सबको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। समकालीन वैश्विक परिदृश्य को देखें तो तमाम देश अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अमेरिका में विभिन्न देशों से घुसपैठ कर आए हुए सभी व्यक्तियों को जबरन उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी करीब 13 लाख अफगानों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। मलेशिया से भी बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबर आ रही है। ऐसे माहौल में भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशियों और म्यांमार से रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

फिलहाल विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है, उससे लगता है कि हम शायद कुछ हजार बांग्लादेशियों को ही वापस भेज पाएंगे। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत में रहने की स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें तीन बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली, अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों को अलग पहचान पत्र दिए जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें देश में रहने और काम करने की अनुमति हो। दूसरी, वे भारत में अचल संपत्ति न खरीद सकें और तीसरी उन्हें किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार न हो। भारत सरकार को यह भी साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे। बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी होगी। बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में भूमि लेने से सिलीगुड़ी कारिडोर की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी।

गृहमंत्री बार–बार कहते हैं कि भारत, कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी घुसा चला आए और यहीं बसेरा बना ले। धर्मशाला तो हमारा देश बन चुका है। देखना यह है कि इस धर्मशाला की सरकार कितनी सफाई कर पाती है।

और बढ़ी वायु सैन्य शक्ति की महत्ता

अजय कुमार

आपरेशन सिंदूर ने भारत की उन क्षमताओं को साबित किया कि पाकिस्तान की धरती पर कदम रखे बिना भी उसके भीतरी इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। अमेरिका और इजरायल ने भी ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों के जरिये ऐसी ही क्षमताएं दिखाई। तुर्किये से लेकर रूस जैसे देश अपनी वायु सैन्य शक्ति विशेषकर ड्रोन जैसी तकनीक पर भरोसा करते हैं। वायु और अंतरिक्ष में किसी देश की क्षमताएं ही उसकी सामरिक शक्ति को निर्धारित कर रही हैं, क्योंकि इसके जरिये सुदूरवर्ती जगह से भी पूरी सटीकता एवं तत्परता से हमला कर दुश्मन को क्षति पहुंचाई जा सकती है। अतीत में युद्ध संसाधनों की दृष्टि से जमीन कब्जाने के लिए लड़े जाते थे, जिसमें जमीन पर सक्रिय सैन्य बलों के लिए वायु शक्ति सहायक की भूमिका निभाती थी। हालांकि जमीन कब्जाने के साथ और जटिलताएं जुड़ी होती हैं, जैसे उस पर काबिज होने के बाद वहां गवर्नेंस भी कई बार बोझ बन जाती है। स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है जो अक्सर गुरिल्ला युद्ध का रूप ले लेता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। अपने उपनिवेशों से ब्रिटेन का निकलना, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका का पलायन और अफगानिस्तान से सोवियत संघ का पीछे हटना यही साबित करता है कि क्षेत्रीय कब्जे में गवनेंस का अंतर्निहित बोझ छिपा होता है। यही कारण है कि आधुनिक समर नीति में युद्धों का स्वरूप बदल गया है। इसमें परंपरा से इतर अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित होता है।

समय के साथ वायु सैन्य शक्ति को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण बदला है। एक समय इसे उकसाने वाला कदम समझा जाता है, लेकिन अब इसे सटीक प्रहार वाली नियंत्रित कार्रवाई के रूप में मान्यता मिल रही है। भारत के बालाकोट और आपरेशन सिंदूर जैसे अभियान से लेकर ईरान

पर अमेरिका–इजरायल की बमबारी यही साबित करती है कि वायु– सैन्य शक्ति टकराव को व्यापक रूप से बढ़ाए बिना ही दुश्मन को घर में घुसकर दंडित करने में उपयोगी साबित होती है। चूंकि ऐसे हमले मुख्य रूप से खुफिया जानकारी पर आधारित चिह्नित आतंकी या सैन्य इलाकों को निशाना बनाकर किए जाते हैं तो इसमें आम जन हानि की आशंका भी घट जाती है। युद्ध का

बुनियादी सिद्धांत ही यही है कि दुश्मन आपके हमले से चौंक जाए। वायु सैन्य शक्ति चौंकाने वाले इस पहलू को सुनिश्चित करती है। यह जितनी गति, तत्परता और सटीकता से लक्ष्य को साधती है, उसकी किसी अन्य पारंपरिक सैन्य शक्ति से तुलना संभव नहीं। इसके जरिये दुश्मन के कमांड सेंटर, आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचाकर उसकी कमर तोड़ना संभव है।

वायु सैन्य शक्ति भी समय के साथ बहुत उन्नत होती गई है। पूर्व में मिग–21 जैसे विमान बेस से केवल कुछ सैकड़ों किमी दूर तक ही संचालित हो सकते थे। आज लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले. बमवर्षक, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों के साथ ही हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा ने हजारों किमी दूर सुदूरवर्ती इलाकों तक मार करने की क्षमता, दिलाई है और वह भी दुश्मन के वायु क्षेत्र में प्रवेश किए बिना। मिसाइलें तो 1,000 किमी से भी दूर तक निशाना लगा सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें तो कम समय में ही काम निपटा सकती हैं। बी–52 और राफेल जैसे विमान हवा में ही ईंधन– भरकर घंटों तक उड़ते हुए महाद्वीपों की सीमा को पार कर सकते हैं। एमक्यू–9 रीपर जैसे ड्रोन दिन भर से अधिक तक अपने लक्ष्य के ऊपर मंडरा सकते हैं।

निःसंदेह भारत ने अपनी वायु सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी की है और यह क्रम निरंतर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें चीन को लेकर अपनी सतर्कता भी बढ़ानी होगी, जिसने अपनी सामरिक, शक्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। चीनी वायु सेना के पास 200 से अधिक जे–20 स्टील्थ फाइटर्स हैं और पिछले 15 वर्षों में उसने आधुनिक लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े को तीन गुना तक बढ़ाया है। एच–6के बमवर्षक के साथ लंबी दूरी की उसकी मारक क्षमताएं बढ़ी हैं तो वाई–20 ट्रांसपोर्ट एयक्राफ्ट के जरिये सैनिकों और रसद सामग्री को तेजी से कहीं भी पहुंचाने की उसकी क्षमता में इजाफा हुआ है। चीन ने लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली पीएल–15 जैसी मिसाइल विकसित की है और उसके उन्नत संस्करणों को तैयार करने में भी लगा हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी वह भारी दांव लगा रहा है। चीन के मिसाइल लांचर भी 2000 के बाद दोगुने से अधिक हो गए हैं। उसका बायडू सैटेलाइट सिस्टम सामरिक मोर्चे को लक्षित करने और नेविगेशन से लेकर संचार सुविधाओं में सहयोग करता है।

पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकियों को देखते हुए भारत की चुनौतियों और बढ़ जाती हैं। इसलिए भारत को न केवल अपनी मौजूदा रक्षा प्रणालियों, बल्कि आधुनिक क्षमताओं के विकास को लेकर भी तत्परता का परिचय देना होगा। इसमें एएमसीए, एलसीए, एमके– टू, लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, एमएएलई और एचएएलई ड्रोन और हवा में ईंधन भरने की अत्याधुनिक तकनीकों को प्राथमिकता में रखना होगा। एडवांस रडार और सेंसर सुइट्स, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम्स के साथ ही पूर्णतया सुरक्षित एवं एआइ–संचालित कमांड एवं कंट्रोल नेटवर्क विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंतरिक्ष मोर्चे पर भारत को सैटेलाइट निगरानी, नाविक, संचार, अल–वार्निंग और एंटी–सैटेलाइट क्षमताएं विकसित करनी होंगी। वायु रक्षा प्रणालियों का एकीकरण और विभिन्न सैन्य बलों में उनके उपयोग को सुगम एवं लचीला बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्वदेशी शोध एवं विकास में निरंतर निवेश बढ़ाना होगा। सार्वजनिक–निजी भागीदारी भी मजबूत बनाई जाए। खरीद प्रक्रिया को गति देनी होगी। वायु और अंतरिक्ष क्षमताएं ही अब संहारक एवं निवारक क्षमताओं को निर्धारित कर रही हैं तो भारत प्राथमिकता के आधार पर अपने औद्योगिक आधार को सक्रिय एवं सशक्त करते हुए ऐसी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे।

आनंद का विज्ञान योग

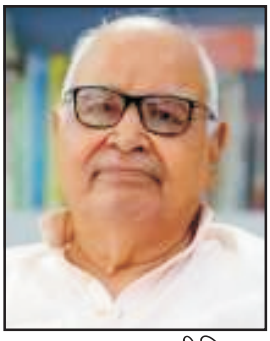

हृदयनारायण दीक्षित

योग आनंद का विज्ञान है। पतंजलि के योगसूत्र में "चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग" कहा गया है। चित्तवृत्ति के प्रभाव में ही संसार दुखमय है। आधुनिक विश्व में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। तनाव और अवसाद बढ़े हैं। क्रोध उफना रहा है। मनुष्य अकेला है। परिवार टूट रहे हैं। आस्थाएं धीरज नहीं देती। आत्महत्याएं बढ़ी है। हिंसा युद्ध रक्तपात भी लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया में अनेक आस्थाएं हैं और अनेक विश्वास। सबके अपने सत्य और विश्वास हैं। आस्था और विश्वास को लेकर हो रहे रक्तपात विश्वमानवता के लिए खतरा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युग है लेकिन वैज्ञानिक शोधों ने हत्या और हिंसा के नए उपकरण दिए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य का पथ आसान हुआ है लेकिन जीवन का शिव और सुन्दर फिसल गया है।

वैज्ञानिक शोधों की अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा होती है। चिकित्सा विज्ञान के शोध मनुष्य के लिए हितकर भी है। अन्य वैज्ञानिक शोध भी विश्व स्तरीय चर्चा का विषय बने हैं लेकिन आज जैसी अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा योग दर्शन की है वैसी चर्चा यूनानी दर्शन के दिग्गजों के निष्कर्षो की भी नहीं हुई–न अरस्तू, सुकरात या प्लेटो की और न ही थेल्स, अनसिक्मेनस, हिराक्लिटस या पाइथागोरस की ही। कांट दर्शन की भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा नहीं हुई लेकिन योग दर्शन का नगाड़ा बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को धन्यवाद। दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। समूचा भारत योग गंध से हहरा रहा है। योग ऋग्वेद के उगने के पहले से परम स्वास्थ्य का मार्ग था। गीता (6.21) में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को योग का लाभ बताया "योग से प्रशान्त हुआ आत्म बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य सुख प्राप्त करता है। बुद्धि और इन्द्रिय सुख से परे परम आनंद को भी प्राप्त करता है।" योग साधक संसार को दुखमय नहीं आनंदमय देखता है। आनंद पाता है और आनंद बांटता भी है। योग आनंद का विज्ञान है। भारत के 8 दर्शनों में एक योग दर्शन भी है। प्रकृति आनंद से भरीपूरी है लेकिन मनीषियों ने संसार को दुखमय बताया है। दुख और आनंद साथ–साथ नहीं रह सकते। संसार वस्तुतः हमारे मन का सृजन है। प्रकृति सदा से है। आनंद से भरीपूरी होने के कारण ही वह सतत् सृजनरत है। संसार इसी का भाग है। तो भी हम आनंद के स्रोत से वंचित हैं। ऐसा क्यों है? बीच में चित्त की बाधा है। योग चित्त अतिक्रमण का ही तंत्र है। चित्तवृत्ति का परदा उठे तो आनंद ही आनंद।

पतंजलि ने योग सिद्धि के अनेक लाभ बताएं हैं। सुन्दर स्वास्थ्य प्राथमिक है। बुद्धि का अनंत प्रज्ञा से जुड़ना बड़ा लाभ है। पतंजलि ने इसके लिए आधे से भी छोटा श्लोक लिखा है–"ऋतम्भरा तत् प्रज्ञाः"। तब प्रज्ञा ऋत से भर जाती है। ऋत प्रकृति का संविधान है। यही सत्य भी है लेकिन ऋतम्भरा में सत्य के साथ सौन्दर्य और शिव भी है। योग सिद्ध व्यक्ति की लाभ हानि सोंचने की परिभाषा बदल जाती है। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, "योग से प्राप्त आनंद से बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं।" (गीता 6.22) वे आगे योग की खूबसूरत परिभाषा करते हैं "दुख संयोगं वियोग योगं संजिज्ञम्–दुख संयोग से वियोग हो जाना ही योग है।" (वही 6.23) श्रीकृष्ण और अर्जुन के साथ हुए मित्रवत सम्वाद में योग विज्ञान की सरलतम झांकी है। लेकिन अर्जुन

तो भी संतुष्ट नहीं होता। अर्जुन हमारे आपके जैसा सामान्य व्यक्ति था। योग विज्ञान सुनने से ही नहीं समझा जा सकता। योग बातों–बातों का बतरस नहीं है, इसके लिए प्रगाढ़ अभ्यास चाहिए। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा, "आपने जो समत्व भाव वाला योग समझाया है, मनचंचलता के कारण मुझे उसका कोई मजबूत आधार नहीं दिखाई पड़ता। मन चंचल होता है, शक्तिशाली और हठी होता है, मन को वश में करना वायु को वश में करने की तरह बहुत कठिन है। (वही 33 व 34)" अर्जुन बेशक योद्धा है, लेकिन मन चंचलता के रहस्यों से परिचित है।

मन स्थिरिता आसान कर्म नहीं है। मन अपनी चलाता है, बुद्धि उसी की पिछलग्गू हो जाती है, हम मनमानी करते हैं, हमारी बुद्धिमानी भी मनमानी की पूरक होती है। मन की ताकत बड़ी है। उसे प्रशिक्षित करने के बाद ही बुद्धि के अनुरूप लाया जा सकता है। वरना मन मनमानी ही कराता है। श्रीकृष्ण ने मनचंचलता की बात स्वीकार की "निस्संदेह मन को वश में करना बहुत कठिन है, यह चंचल है लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है–अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।" (वही 35) गीता का यह श्लोक पतंजलियोगसूत्र से मिलता–जुलता है। पतंजलि का योग 'चित्तवृत्ति निरोध' है। श्रीकृष्ण का योग 'मनोनिग्रह' है। दोनो का मन्तव्य एक है। श्रीकृष्ण 'अभ्यास और वैराग्य' का मन्त्र देते हैं। पतंजलि की भाषा भी वही है "अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः–अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का नियंत्रण संभव है।" (पतंजलियोगसूत्र 1.12) पतंजलि की शैली वैज्ञानिक है, वे आगे अभ्यास की परिभाषा बताते हैं "इन दो (अभ्यास, वैराग्य) में अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का प्रयास है–तत्रस्थितौ यत्नो अभ्यासः।" (वही 13) यहां अभ्यास का मतलब योगासन नहीं, स्वयं के कर्म में स्थिर होने का प्रयास है।

अभ्यास स्वयं के प्रति सजग चेष्टा है, वैराग्य इच्छा शून्यता है। अभ्यास और वैराग्य चित्त को संयत करते हैं। असली बात है संयत चित्त। योगासन और ध्यान इसी के उपकरण हैं। व्यक्तित्व की पूरी ऊर्जा को एकाग्र करने का नाम अभ्यास है। फिर वैराग्य बताते हैं, "ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सजग प्रयास से भोग आसक्ति के प्रति वितृष्णा वैराग्य की प्रथम अवस्था है, पुरूष के अंतरतम का बोध होने पर सभी इच्छाओं का विलीनीकरण वैराग्य की पूर्णता है।" (वही 15 व 16) श्रीकृष्ण ने कहा, "असंयत के लिये योग कठिन है, लेकिन संयत व्यक्ति संकल्पबद्ध होकर योगलब्ध हो जाता है।" (गीता 6.36) अभ्यास, वैराग्य, असंयत और संयत चित्त मनुष्य की अंतर्यात्रा के पड़ाव हैं।

पतंजलि योग सूत्र सुव्यवस्थित दर्शन है और यथार्थ विज्ञान भी। दर्शन के आत्मिक अनुभव में मन की चंचलता बाधा है। बाधाएं और भी हैं। पतंजलि ने योग सूत्र (30) में बताया है कि "रोग, प्राणहीनता, संशय, प्रमाद, आलस्य, आसक्ति, भ्रान्ति और अस्थिरता बाधाएं हैं। दुख, निराशा, कपकपी और अनियमित श्वसन लक्षण हैं।" यहां 'रोग' ध्यान देने योग्य हैं। पतंजलि वैद्य या चिकित्सक नहीं थे। चरक संहिता आयुर्विज्ञान की प्रख्यात ग्रंथ है। बताते हैं–"बिना रोग का होना सुख है और रोग दुख है।" आगे स्वास्थ्य के बारे कहते हैं "जब मन और बुद्धि का समान योग रहता है तब मनुष्य स्वस्थ रहता है जब इनका अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होता है तब रोग।" रोग मन और बुद्धि के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के परिणामी है। योग परम स्वास्थ्य है। प्राण और शरीर का योग जीवन है। प्राण का कम होना जीवनी शक्ति का घटना है। आलस्य प्राण शक्ति घटाता है, आसक्ति बढ़ाता है। भ्रान्ति और अस्थिरता मन विक्षेप लाते ही हैं। पतंजलि ने मनुष्य का रहस्यपूर्ण विवेचन किया है और परम स्वास्थ्य के प्राचीन दर्शन को पुनर्जीवित किया है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से स्वस्थ व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता। आनंदित व्यक्ति सृजन करता है और तनावग्रस्त व्यक्ति ध्वंस। योग तनावग्रस्त विश्वमानवता को भारत का प्रशांत उपहार है।

भारतीय राष्ट्रवाद में स्वामी विवेकानंद का योगदान

स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के देदीप्यमान सितारे थे। उनका जीवन मानवता और भारतीयता के लिए प्रेरणास्पद था। वे उदारवाद हिन्दू धर्म के प्रर्वतक थे। उनकी सोच वेदान्त उपनिषद, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता पर आधारित थी । उनका दिया गया संदेश सभी धर्मों की अच्छी बातों पर आधारित था। उनका भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था। बिना सच्ची राष्ट्रीयता के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। उनके अनुसार धर्म, समाज, संस्कृति, मानवता आदि राष्ट्रीयता के प्रमुख अंग हैं। विश्व हिंदू सभा, शिकागों में 1893 ई0 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का परचम लहराया जिसके बाद पूरा विश्व उनके विचारों का कायल हो गया। उनका भारतीय राष्ट्रवाद नवहिन्दूवाद का प्रतीक था, जिसमें हिंदुत्व, उदारवाद, सहिष्णुता, कर्मवाद आदि सम्मिलित है। भारतीय स्वतंत्रता में तथा राष्ट्रवाद के विकास में स्वामी विवेकानंद के दर्शन का प्रमुख योगदान है।

स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है । इनका चिंतन हमें सौ साल के बाद भी ऊर्जा व जोश से भर देता है। विवेकानंद की सोच, उनका दर्शन और धार्मिक व्याख्याएँ आधुनिक व स्पष्ट हैं। धार्मिक होते हुए भी उनकी सोच प्रगतिशील और भविष्य की ओर देखने वाली है। अपने कर्म, जीवन, लेखन, भाषण और संपूर्ण प्रस्तुति में, उनका एक आदर्श प्रबंधक और कम्युनिकेटर का स्वरूप प्रकट होता है। आधुनिक काल में भारतीय समाज में जिन महापुरूषों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, उनमें स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर है उन्होंने वेद उपनिषद की व्याख्या कर आधुनिक युग के सामने एक नया मार्ग सुझाया जिस पर चलकर मानव समाज ऊँचे लक्ष्यों की ओर अग्रसरित हो सकता है। अपने उपदेशों व क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना व स्वाभिमान की भावना को उत्पन्न किया।

राष्ट्रीय जागृति अर्थात भारत में रहने वाले समूचे जनसमुदाय के जागरण का मूलस्रोत स्वामी विवेकानंद के संदेशों में पाया जाता है। उनका राष्ट्रवाद राजनीतिक

राष्ट्रवाद ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय पहचान व भारतीयों में सांस्कृतिक एकत्व का निर्माण करता था। विवेकानंद की धारणा थी कि राष्ट्र की शक्ति उसके जन साधारण पर निर्भर करती है और अपने कार्य के आरंभ से ही उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा था। उन्होंने अधिकांश भारत का भ्रमण किया था ओर जहाँ भी वे जाते, वहाँ के लोगों के साथ तादाम्य स्थापित कर उन्हें अपना बना लेते थे । विवेकानंद ऐसे भारतीय थे जिनकी नजर में सभी भारतवासी भाई थे। उनका मानना था कि भारतीय लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के है और इससे एकजुट होने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने करूणा, सेवा और त्याग को राष्ट्रीय आदर्श के रूप में मान्यता दी।

विवेकानंद का राष्ट्रवाद सार्वभौमिकता और मानवतावाद पर आधारित था। उनके राष्ट्रवाद का आधार धर्म, भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता थी। लोगों का आध्यात्मिक एकीकरण और आत्मा की आध्यात्मिक जागृति ही उनके लिए राष्ट्रवाद थी। वेद और उपनिपद को भारतीय धर्म की आधार भूमि मानते थे। वे वेदांत को भारतीय दर्शन का अक्षय कोप मानते थे। उन्होंने वेदांत व उपनिपद के सिद्धांतों को भारतीय संस्कृति एवं भारतीय

चरित्र के स्वभाव के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया। रूढ़ियों, आडम्बरों और बाह्याचारों से ऊपर उठकर स्वामी विवेकानंद ने धर्म की विलक्षण व्याख्या की। अपनी वाणी व विचारों से भारतीयों में अभिमान जगाया कि हम अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी है। हमारे धार्मिक ग्रंथ सबसे उन्नत और हमारा इतिहास महान है। उन्होंने भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को जागृत किया।

विवेकानंद का मानना था कि भारत में धर्म स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक रचनात्मक शक्ति है। उनके लिए गरीबों, दलितों, बीमारों व अज्ञानियों में भगवान देखना और उनकी सेवा करना ही धर्म है। राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए विवेकानंद का ध्यान युवाओं पर केंद्रित था। उन्हें युवा वर्ग पर अटूट विश्वास था व स्त्रियों के प्रति अगाध आस्था थी। विवेकानंद ने एक नये प्रगतिशील समाज की कल्पना की जिसमें धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य – मनुष्य में कोई भेद नहीं हो।

मनुष्य मात्र की बुनियादी एकता और समता की प्रतिष्ठित करने वाला उनका यह सूत्र मानवतावाद की स्थापना का एक बड़ा अभियान था। समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही अन्यत्र ढूंढा जा सकता है।

विवेकानंद एक ऐसे युगपुरुष के रूप में सामने आते हैं जिनकी बातें आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक होते हुए दीखती है। धर्म के स्वरूप को स्थापित कर उन्होंने जड़ता को तोड़ने का और नए भारत के निर्माण पर जोर दिया था। भारतीय समाज में आत्मविश्वास भर कर उन्हें हिंदुत्व के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को स्वीकारा गया है और सभी धार्मिक विचारों का आदर करने का भाव है। विवेकानंद का उदारवादी हिंदू धर्म, नवहिंदूवाद है, जिसमें सभी धर्मों व संस्कृतियों के उच्च आदर्शों का दर्शन है, जो वेदांत व उपनिप्द पर आधारित है।

विवेकानन्द ने 1893 में शिकागों में संपन्न 'विश्व धर्म सम्मेलन' में लोगों को यह बताया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाये तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। हिन्दू धर्म की नयी उदारवादी व्याख्या कर अपने विचारों तथा चिंतन से सारी दुनिया को परिचित करवाकर उन्होंने हिंदू धर्म का परचम लहराया।

विवेकानंद भारत को एक जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन्हें भारतीय जनमानस की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने राष्ट्र की युवा पीढ़ी को राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रेरित किया। युवाओं में उन्होंने आत्मविश्वास, गौरव की भावना को जागृत किया। वे चाहते थे कि युवा वर्ग आगे आएं और भारत को विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में सबसे आगे लाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें ।

स्वामी विवेकानंद कट्टर राष्ट्रवादी थे किंतु उनका राष्ट्रवाद मानवता का पोषक था। उनके राष्ट्रवाद का लक्ष्य था समग्र मानव–जाति की सेवा के साथ–साथ भारतीयों की दीनता और अज्ञानता को दूर करना। स्वामीजी का राष्ट्रवाद धर्म और कर्म के दो मुख्य आधारों पर खड़ा है। राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त दोपों को दूर करने के लिए उन्होने धर्म को मान्यता दी । धर्म को वो मनुष्य में निहित दैवत्व का प्रतीक मानते थे और उसे अनुभव और अनुभूति की वस्तु स्वीकार करते थे। उन्होंने सभी धर्मो के मूलभूत एक तत्व की समानता का अनुभव किया। मनुष्य के समग्र विकास के लिए स्वामी जी ने वेदांत का सहारा लिया और अद्वैत वेदांत को व्यावहारिक बनाने के लिए उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की। विवेकानंद कहते थे कि विभिन्न धर्मो के प्रतीक भले ही अलग–अलग हो परंतु उनका सार एक ही है। विशेषकर हिन्दू धर्म ने इस विविधता को मान्यता दी है और इस यथार्थ को समझा है। उनका राष्ट्रवाद मिश्रित और बहुलतावादी था। वस्तुतः विवेकानंद ने भारतीयों के उत्थान के लिए जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी, उसके मूल में मानवतावाद, आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक नवजागरण है जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने वेदांत का सहारा लिया। उनका राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण से शुरू होता है। राष्ट्र निर्माण का कार्य अपने नागरिकों के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण से प्रारंभ होता है। विवेकानंद का मानना था कि देश की युवा पीढ़ी अगर बलशाली होगी तो वे अपने मार्ग में आने वाले किसी भी विरोध का सामना कर सकेंगे ।

युवाओं व प्रत्येक भारतीय को उन्होंने कर्मवाद का

संदेश दिया। उन्होंने युवाओं में भारतीय होने का गर्व पैदा कर किया। साथ ही भारतीय जनमानस को प्रेम, दया, करुणा, सेवा, आत्मविश्वास, साहस आदि का महत्व समझाया। वेद, उपनिषद् व पुराणों के द्वारा उन्होंने पुरी दुनिया में भारतीय चिंतन की नवीन व्याख्या कर, भारतीय गौरव को पुनः स्थापित किया।

स्वामी विवेकानंद का दर्शन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व मानवता के हित के लिए सार्थक है । उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने विश्व के समस्त देशों व मनुष्यों को मानवता को संदेश दिया था । वे चाहते थे कि विश्व के सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें तथा समझें। उन्होंने विश्व – बंधुत्व की भावना को उजागर किया था। वास्तव में विवेकानंद विश्व – गुरु थे। इन्होंने पाश्चात्य देश में, वहां के निवासियों के समक्ष भारतीय धर्म की व्याख्या कर, इसकी महानता को स्थापित किया था। विवेकानंद का स्पष्ट मत था कि केवल सर्वधर्म समभाव से मानवता का कल्याण हो सकता है। इसमें नैतिकता, मानवतावाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का एक सर्वभौमिक रूप है। विवेकानंद ने अपने विचार, आदर्श व सिद्धांत के द्वारा भारत ही नहीं, अपितु विश्व को भी एक नई दिशा प्रदान की थी। हिंदू धर्म में विद्यमान दर्शन, मानवता, विश्व–बंधुत्व व सहिष्णुता, राष्ट्रवादी विचारों से लोगों को प्रभावित किया था।

वस्तुतः विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता व नैतिकता पर आधारित है जो भारतीयों की जीवन–शक्ति है। विवेकानंद को संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा, अध्यात्म व आत्मविश्वास की मिसाल कहा जा सकता है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जा सकता है।

स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रेरक बातों से भारतीयों में स्वाधीनता के लिए जान फूंक दी जो धर्म तथा कर्म पर आधारित था। भारतीय राष्ट्रवाद में स्वामी विवेकानंद का योगदान अविस्मरणीय है। आने वाले समय में उन्हें लोग सदा पूजते रहेंगे।

(सौजन्य– स्मिता)

पूर्व सैनिक सेवा परिषद गीत

हम भारत के पूर्व सैनिक,
नई प्रेरणा लाये हैं।
देश की रक्षा करते थे,
अब इसे सजाने आये हैं।
बर्फ की चोटी, तपती रेती,
सागर हो या हो खाई।
शत्रु पोत और टैंक विमानों,
की देखो शामत आई।
भारत के जल–थल नभ सारे,
सदा बचाते आये हैं।। हम...
समर भूमि से कर्म भूमि को,
अब हम बढ़ते जायेंगे।
छुआ–छूत और ऊँच–नीच को,
जड़ से दूर भगायेंगे।
अपना भारत सुखी बली हो,
शिव संकल्प संजोये हैं।। हम...
सामाजिक समभाव सुरक्षा,
निर्बल क्यों भयभीत रहें।
सन्तति हैं सब भारत मां की,
सबके मन में प्रीति रहे।
संगठना में महाशक्ति है,
मंत्र यही अपनाये हैं।। हम...
अपने श्रम, अपने पौरुष से,
सब बाधायें दूर करें।
सद्शिक्षा और सद्विचार से,
मानवता को पुष्ट करें।
महान राष्ट्र था, पुनः बनेगा,
लक्ष्य यही ले आये हैं।।
हम भारत के पूर्व सैनिक,
नई प्रेरणा लाये हैं।
!!भारत माता की जय !!

हमारे उद्घोष

पूर्व सैनिक– जिन्दाबाद, जिन्दाबाद
पूर्व सैनिक आयें हैं– नई रोशनी लायें है।
पूर्व सैनिक की क्या पहचान– सेवा, साहस और सम्मान

चीन–पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़

मेजर जनरल जगतबीर सिंह (वेटरन)

आपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सैन्य बल पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुटे हुए थे तो चीन की ओर से उसे पूरी मदद मिल रही थी। केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी प्रोपेगंडा को आगे बढ़ाने में भी चीनी मीडिया पुरजोर प्रयासों में लगा था। इसमें एक कारण उन चीनी हथियारों की कथित सफलता को रेखांकित करना भी था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही थी। पाकिस्तान को चीन के हथियारों से लेकर तकनीकी समर्थन का बढ़ता सिलसिला भारत की चुनौतियां बढ़ाने वाला है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने हाल में चीन–पाकिस्तान की इस दुरभिसंधि के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन के अलावा साइबर आपरेशन और नेटवर्क आधारित वारफेयर एलिमेंट्स पर चीनी सैन्य प्रतिष्ठान की छाप दिखी। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी आइएसआर सिस्टम ने पाकिस्तानी सैन्य बलों को रियल टाइम डाटा, वस्तुस्थिति से जुड़ी जानकारियां और निगरानी क्षमताएं भी उपलब्ध कराईं। यहां तक कि मछली पकड़ने वाले चीनी बेड़े का इस्तेमाल भी भारतीय नौसेना पर नजर रखने के लिए किया गया, जबकि पाकिस्तानी नौसेना अपने तटों तक ही सीमित रही।

जब सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ स्तर पर वार्ता जारी थी तो पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमें पता है कि आपके सैन्य संसाधन कहां, कितनी मात्रा में लगे हुए हुए हैं, इसलिए अनुरोध है कि उन्हें हटा लिया जाए। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास भारतीय सैन्य तैनाती से जुड़ी काफी सूचनाएं थीं, जो उसे किसी और से नहीं, बल्कि चीन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थीं। आपरेशन सिंदूर चीनी रक्षा उद्योग के लिए अपनी क्षमताओं के परीक्षण का भी एक पड़ाव बना, जिसमें वास्तविक युद्ध की स्थिति में उसके उपकरणों की परख होनी थी। बीते पांच साल में पाकिस्तान द्वारा

खरीदे गए रक्षा उपकरणों में करीब 81 प्रतिशत चीन से लिए गए। इस तरह चीन ने पाकिस्तान को अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें उसके हथियारों का अन्य हथियार प्रणालियों के आगे प्रदर्शन दिख जाए। इससे सबक लेकर चीन अपनी रक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाएगा, जिसका लाभ अंततः पाकिस्तान जैसे खरीदारों को ही मिलेगा।

आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को एक साथ तीन मोर्चों पर जूझना पड़ रहा था। पाकिस्तान से तो सीधा मुकाबला था ही, चीन से हरसंभव सहयोग के अलावा तुर्किये से उसे ड्रोन एवं प्रशिक्षित कर्मियों के जरिये भी मदद मिली। हाल के वर्षों में चीन ने पाकिस्तान का लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बचाव करते हुए उसे आधुनिक मिसाइलें और परमाणु तकनीक उपलब्ध कराई है। आपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम हथियार प्रणालियों के अलावा चीनी बायडू नेविगेशन सिस्टम ने भी पाकिस्तान को बड़ी मदद पहुंचाई। इसमें पीएल–15 के लिए मिसाइल गाइडेंस जैसी सुविधा भी शामिल रही। यह दर्शाता है कि पाकिस्तानी सामरिक संचालन में चीनी प्रणालियों का सीधा जुड़ाव बढ़ रहा है। कुछ रिपोर्ट यह इशारा भी करती हैं कि स्वीडिश साब 2000 एरिये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यूएंडसी) प्लेटफार्म की चीनी सिस्टम के साथ जुगलबंदी के जरिये भारतीय विमानों को निशाना बनाया गया। स्पष्ट है कि अलग–अलग स्रोतों वाली प्रणालियों को भी चीनी तकनीक के साथ जोड़कर उनका उपयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान को पांचवीं पीढ़ी के जे–37 चीनी लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक के अंतर्गत भी चीन ने ग्वादर जैसे बंदरगाह के अलावा सामरिक महत्व का दूसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान में विकसित किया है। यह पाकिस्तान की आर्थिकी के साथ ही उसकी सैन्य क्षमताओं को लाभ पहुंचाता है। अपनी भू–सामरिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान महाशक्ति बनने की चीनी महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सीपैक और सामुद्रिक सिल्क रूट के जरिये बीजिंग को अहम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है।

इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक लंबे अर्से से चीन और पाकिस्तान के साथ भी भारत का सीमा विवाद चला आ रहा है। इस कारण अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमें सैन्य बलों की व्यापक तैनाती रखनी पड़ती है। गलवन संकट के बाद से तनातनी घटाने के कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन सैनिकों की वापसी पूरी तरह नहीं हो सकी है। आपरेशन सिंदूर के बाद से नियंत्रण रेखा पर भी संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ती दिखीं। आपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भी बिना कोई औपचारिक लक्ष्मण रेखा लांघे अपनी क्षमताओं को परखा। यह भारत की काट के लिए पाकिस्तान की सामरिक एवं पारंपरिक क्षमताओं को बढ़ाने की चीनी रणनीति में एक अहम मोड़ रहा। इन दोनों देशों की साठगांठ में. कोई पर्दा शेष नहीं रहा।

आपरेशन सिंदूर के सबक स्पष्ट, हैं कि भारत को खतरे के आकलन, सैन्य आधुनिकीकरण और परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं को और दुरुस्त बनाना चाहिए। इसने भारत के सामरिक गुणा–गणित और रक्षा नियोजन जैसे पहलुओं को बुनियादी रूप से बदल कर रख दिया, क्योंकि दो मोर्चों पर लड़ाई कोई कपोल–कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता का रूप लेती दिख रही है। इसलिए हमें अपनी आर्थिकी को मजबूत बनाते हुए सैन्य क्षमताओं को सशक्त बनाना ही होगा। तभी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। चीन–पाकिस्तान की जोड़ी और उनका जुड़ाव निरंतर खतरनाक होता जा रहा है। इसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं कि इस क्षेत्र में चीन का भू–राजनीतिक फोकस भारत की राह में रोड़े बिछाने के लिए पाकिस्तान को अपने पिट्ठू के रूप में इस्तेमाल करते रहना है। आपरेशन – सिंदूर ने यह भी दर्शाया कि नई लड़ाइयां पुराने तौर–तरीकों से नहीं लड़ी जाएंगी। अब सैन्य टकराव के साथ ही साइबर, आर्थिक, कानूनी, सूचना और छद्म युद्ध जैसे मोर्चों पर भी मुकाबला करना होगा। ऐसे परिदृश्य में चीन पर्दे के पीछे रहते हुए भी प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपने दांव आजमाता रहेगा। भारत के पास इन दोनों देशों की चुनौती का माकूल तोड़ निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

कारगिल विजय यात्रा–भारत के वीर सपूतों को नमन

–रियर एडमिरल (डॉक्टर) राजवीर सिंह (सेवानिवृत्त)

इस वर्ष हम भारतीय सेनाओं की पाकिस्तान के सेनाओं पर कारगिल युद्ध के दौरान विजय की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 84 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में भारत ने अंततः 26 जुलाई 1999 को यह विजय प्राप्त की। इस दिन, राष्ट्र उन भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने युद्ध के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कारगिल विजय दिवस युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मरण, राष्ट्रीय गौरव और कृतज्ञता का क्षण है। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने लद्दाख के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, और फिर भारतीय सेना को इस युद्ध में दुश्मन को अपनी सीमा से बाहर करने के लिए युद्ध के शुरुआ करनी पड़ी। पाकिस्तान ने शुरू में दावा किया कि आक्रमणकारी स्वतंत्र आतंकवादी समूहों के सदस्य थे, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की सेना इस घुसपैठ के पीछे थी। 26 जुलाई 1999 तक, आगे बढ़ती भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया।

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद (एबीपीएसएसपी), पूर्व सैनिकों का एक अखिल भारतीय संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए पूर्व सैनिकों के अंतर्निहित अनुशासन, सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा, समर्पण और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दिशा प्रदान करना है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में संगठन राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों का मानव संसाधन के रूप में उपयोग करने का प्रयास करता है। हर साल पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल जाता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस वर्ष, एबीपीएसएसपी द्वारा यह यात्रा 1 जुलाई से 7 जुलाई 25 तक आयोजित की गई। इस लेखक के नेतृत्व में तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना के 48 पुरुषों और महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल 01 जुलाई 25 को श्रीनगर पहुंचा। अगले दिन 02 जुलाई को सुबह हमने श्रीनगर में युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। युद्ध स्मारक पर बड़ी संख्या में अंकित शहीदों के नाम याद दिलाते हैं कि श्रीनगर और घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान की नापाक हरकतों से बचाने के लिए बहुत सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और ये सिलसिला आजादी के बाद से ही जारी है।

श्रीनगर युद्ध स्मारक के समीप ही, 8वीं शताब्दी का पांडरेथन मंदिर है। पांडरेथन की पहचान सम्राट अशोक द्वारा स्थापित श्रीनगर की राजधानी के मूल स्थल के रूप में की गई है। शताब्दी के दौरान, राजधानी को उत्तर–पश्चिम में कुछ दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को पुराणधिष्ठान कहा जाता था, जिसका संस्कृत में अर्थ पुरानी राजधानी है, और श्रीनगर का उपयोग नई राजधानी के नाम के रूप में किया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि 960 ईस्वी में एक शहर को नष्ट कर दिया था। मंदिर परिसर में की गई खुदाई में कई दो बड़े शिवलिंग, सात गांधार शैली की मूर्तियाँ और एक मूर्ति के पैरों की विशाल चट्टान पर नक्काशी शामिल

हैं । हाल ही में, चिनार कोर को पांडरेथन मंदिर के संरक्षण और कायाकल्प के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। 2021 में, चिनार कोर ने उत्खनित मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक थीम आधार हेरिटेज पार्क बनाया। एबीपीएसएसपी के सदस्यों ने मंदिर का दौरा किया और वहाँ पूजा–अर्चना की। इसके बाद, हमने श्रीनगर स्थित सेना संग्रहालय इबादत–ए–शहादत का दौरा किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 25 पूर्व सैनिकों का एक समूह भी हमारे साथ था, और उनसे बातचीत करके हमें बहुत खुशी हुई। यह संग्रहालय कश्मीर के प्राचीन और आधुनिक इतिहास का भंडार है। कश्मीर के इतिहास को पढ़ने के बाद, हमें एहसास होता है कि कई लोगों ने कई गलतियां की हैं, और यही कारण है कि इस राज्य ने इतनी उथल–पुथल देखी है, जितनी देश के किसी अन्य राज्य ने नहीं देखी।

3 जुलाई को हम सड़क मार्ग से श्रीनगर से द्रास के लिए रवाना हुए। रास्ते में, हम गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग से गुजरे। इस सुरंग को इसी वर्ष 13 जनवरी को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सुरंग सड़क के एक Z आकार के हिस्से को बायपास करती है, जो पहले बर्फ पड़ने से प्रभावित होता था और भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीनों में सड़क बंद हो जाती थी। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की यात्रा करने में पहले टेढ़ी–मेढ़ी सड़क पर घंटों की तुलना में अब केवल 15 मिनट ही लगते हैं। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊँचाई पर स्थित इस सुरंग ने, लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम में रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया है। यह सुरंग बनने से अब यह सड़क, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसे खतरों से प्रभावित नहीं होगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन संभव है। हमने दोपहर में जोजिला दर्रा पार किया और निर्माणाधीन जोजिला सुरंग देखी, जो हिमालय क्षेत्र में भारतीय इंजीनियरों की कार्य परायणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सुरंग पर भी निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, और आशा है कि यह सुरंग वर्ष 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी । जोजिला सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच सड़क मार्ग की दूरी कम करेगी और श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–1 पर निर्बाध सड़क परिवहन सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में श्रीनगर और लद्दाख के बीच बेहतर संपर्क मार्ग स्थापित होने से सर्दी के महीनों में रक्षा सामग्री को पहुंचाने में आसानी होगी और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरण को गति मिलेगी। रात में, हम द्रास में बत्रा ट्रांजिट कैंप (बीटीसी) में रुके।

अगले दिन 4 जुलाई को, हम कारगिल युद्ध स्मारक गए, जो मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले युद्ध नायकों के सम्मान में बनाया गया है। कारगिल युद्ध स्मारक तोलोलिंग पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ से तोलोलिंग हाइट्स, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 (बत्रा टॉप) दिखाई देते हैं, जहाँ कारगिल युद्ध हुआ था। इस स्मारक के प्रांगण में कदम रखना श्रद्धा और मनन की यात्रा पर निकलने जैसा है। स्मारक भारतीय सेनानियों की अदम्य वीरता और शानदार विजय का एक जीवंत चित्रण है। स्मारक की मुख्य विशेषता गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार है जिस पर पीतल की एक प्लेट लगी है जिस पर ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए सभी 545 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं।

जब आप समाधि–शिलाओं की पंक्तियों के बीच से गुजरते हैं, तो उनके बलिदान की गूँज आपके भीतर तक महसूस होती है। इस स्थान पर गुजारे हुए पल आपकी अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और फिर दिल उन वीरों और उनके परिवारीजनों के प्रति कृतज्ञता से भर आता है। अमर जवान ज्योति से लेकर हीरोज वॉल तक, स्मारक का हर कोना अदम्य साहस और बलिदान की कहानी कहता है। स्मारक में कैप्टन मनोज पांडे को समर्पित गैलरी, उस युवा अधिकारी को स्मरण कराती है, जिसे युद्ध के दौरान नेतृत्व के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 4 मराठा लाइट इन्फैंट्री के एक जवान द्वारा हिंदी में स्मारक पर दी गई जानकारी आगंतुकों के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रेरणादायक और विस्मयकारी थी। युद्ध स्मारक पर उनका वर्णन सुनने के बाद, मैं खुद को रोक नहीं पाया और जानकारी के अंत में तुरंत उनकी बेबाक वाकपटुता और मिशन के ज्ञान के लिए उन्हें

बधाई दी। यह घटना इस बात का जीवंत उदाहरण थी कि कैसे विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े भारतीय सेनाओं के जवान एकजुट होकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाते हैं। स्मारक पर, आगंतुक युद्ध के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं का क्रम देख सकते हैं। आगंतुकों को एक वृत्तचित्र भी दिखाया जाता है, जो पूरे युद्ध और उससे पहले की घटनाओं को विस्तार से वर्णन है। यहाँ की यात्रा निश्चित रूप से एक भावनात्मक और उन भारत के सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि थी जो फिर इस लड़ाई के बाद नहीं लौट पाए। द्रास से फिर हम कारगिल गए और वहां हमने कारगिल सेक्टर में विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

5 जुलाई को हम द्रास से श्रीनगर वापस आए। यह संयोग था या ईश्वर का चमत्कार, कि हमें एक पाकिस्तानी सैनिक जिसका मृत शरीर लेने से 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने मना कर दिया था, अब इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में उसकी गौरव गाथा गाई जा रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने 5 जुलाई 2025 को पूरे सैन्य अधिकारियों के साथ, कारगिल शहीद कैप्टन करनाल शेर खान को उनकी 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालाँकि पाकिस्तान ने शुरुआत में कैप्टन शेर खान को पाकिस्तानी सैनिक होने से ही इंकार कर दिया था और भारतीय धरती से उसका शव लेने से इनकार कर दिया था लेकिन भारतीय सेना के एक अधिकारी ने उसकी युद्ध के दौरान दिखाई वीरता का वर्णन लिख कर उसकी जेब में रख दिया था। उसी खत को पढ़कर आज पाकिस्तानी सेना उसे उचित सम्मान दे रही है।

श्रीनगर से कारगिल और वापस सड़क मार्ग से यात्रा करने पर, आप जम्मू–कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे बुनियादी ढाँचे के विकास को देखते हैं। दशकों तक, जम्मू– कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे ने इसे कई राष्ट्रीय सुधारों से अलग रखा, जिससे इस क्षेत्र में निजी निवेश और आर्थिक विकास सीमित रहा। आज, निवेशक कश्मीर को नई रुचि के साथ देख रहे हैं, जिससे पर्यटन, रियल एस्टेट और औद्योगिक परियोजनाओं में विकास हो रहा है। कभी बंद और विरोध प्रदर्शनों से त्रस्त रहने वाले बाजारों में अब शाम को देर तक भीड़ की चहल पहल दिखाई देती है। आज, कश्मीर घाटी, जो कभी पत्थरबाजी की घटनाओं और हड़तालों से त्रस्त रहती थी, एक असाधारण बदलाव देख रही है – संगठित पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद हो गई है, और बाजार डर के बिना फल–फूल रहे हैं। जम्मू–कश्मीर का परिवर्तन केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि लोगों के अपने जीवन, आकांक्षाओं और सम्मान को पुनः प्राप्त करने के तरीके में भी स्पष्ट है। भारतीय सेना आज कश्मीर में पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे होमस्टे, गेस्टहाउस और स्थानीय होटल और रेस्टॉरेंट के विकास को प्रोत्साहन मिला है। वे स्थानीय होटल व्यवसायियों को उनकी सेवाओं में सुधार लाने और पर्यटन क्षेत्र को अधिक पर्यटक–अनुकूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। सेना सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों के आयोजन में भी भूमिका निभाती है, जो जम्मू और कश्मीर की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं और पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करते हैं। सोनमर्ग में, सेना ने शीतकालीन खेल गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे इस क्षेत्र की पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में और वृद्धि हुई है।

यह यात्रा भावनात्मक रूप से बहुत ही सफल रही। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एबीपीएसएसपी के राष्ट्रीय महासचिव ने श्रीनगर, द्रास और कारगिल में सेना के अधिकारियों के साथ सभी व्यवस्थाएँ पहले से ही सुनिश्चित कर ली थीं। हमारी यात्रा के संचालन में शामिल सभी सेना की यूनिटें हमारी मदद करने के लिए तत्पर थीं, कभी–कभी तो अपनी सीमा से बाहर जाकर भी। अंत में, एक पूर्व नौसेना अधिकारी होने के नाते, मैं कश्मीर घाटी और लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के प्रत्येक पुरुष और महिला को प्रणाम करता हूँ। विशेष दुर्गम परिस्थितियों में रहते हुए, जहाँ साँस लेना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भी वे प्रतिदिन आने–जाने वाले रक्षा कर्मियों को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। श्रीनगर, सोनमर्ग और द्रास में अस्थायी शिविरों का प्रबंधन करने वाले सूबेदार मेजरों का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण देश सेवा का एक आदर्श उदाहरण है।

Why do nations acquire nukes: decoding Iran's dilemma

Maj Gen Harsha Kakkar (Veteran)

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission tweeted during the Iran-Israel conflict, 'Iran must never acquire the bomb.' She subsequently welcomed the announcement of a ceasefire by Trump and added, 'We call on Iran to engage seriously in a credible diplomatic process. Because the negotiating table remains the only viable path forward.' Evidently the west appears to believe that they possess the power to determine who can develop nuclear weapons and who should not.

They have also taken it upon themselves to remove regimes which they assume are acting against their interests. To achieve their aims they occasionally exploit global bodies such as the UN to legalize their actions. In recent times, they have begun ignoring the UN and acted on their own.

Wherever the west has interfered, they have left behind a mess or forced to withdraw in defeat. The only nations which are secure are those who possess a deterrent in terms of nuclear weapons. It has hence become an unwritten rule that a nation, with political systems at odds with the west, must possess nuclear weapons or bow to western supremacy to ensure its security, as many monarchies in West Asia have done.

In March 2003, NATO invaded Iraq claiming it possessed Weapons of Mass Destruction (WMD). The sole intent was removal of Saddam Hussein. Saddam Hussein was overthrown, captured, tried and hung, but no WMDs were discovered, a fact known well even before the invasion was considered. Evidently, the intent was not WMDs but possibly oil. Since then, US forces have remained deployed in Iraq's oil fields whose operations are controlled by US companies.

Almost five thousand US troops and over hundred thousand Iraqis have been killed and millions displaced since Saddam Hussein's removal. The ISIS rose in the vacuum created by Saddam's ouster. It needed years and thousands of casualties before they were finally subdued. Iraq remains politically unstable with multiple insurgent groups backed by Iran continuing to operate.

Libya had pursued a nuclear weapons program once Gaddafi assumed power in 1969. Post the cold war, Gaddafi attempted to enhance relations with the west and sought lifting of sanctions. It was compelled to surrender its nuclear weapons program and finally signed an agreement on it in Dec 2003. Without nuclear weapons, Libya was vulnerable to western manipulation.

Following the Arab Spring, which commenced in end 2010 and spread to Libya in 2011, the US pushed a resolution in the UNSC authorizing use of force to protect civilians in Libya. It launched airstrikes and supported anti-Gaddafi forces. Gaddafi was overthrown. Over a decide later Libya remains divided and violence continues unabated, with thousands of civilians killed.

Libya, once the most thriving economy in North Africa is now struggling to survive. Once again, the reason for Gaddafi's removal was Libya's oil resources. When questioned on what

was his biggest mistake as President, Obama stated, 'probably failing to plan for the day after what I think was the right thing to do in intervening in Libya.'

Twenty years in Afghanistan and the US could show nothing. It handed over the country to the same Taliban which it overthrew. Pak was the only nation which gained by playing both sides. As per reports, the US suffered over 2500 dead, 20,000 wounded, while almost forty-five thousand Afghans lost their lives. Currently Afghanistan is no better than what it was in 2001. Osama Bin Laden whom the US hunted for 26/9 attacks, was finally eliminated in Abbottabad in Pakistan.

On obtaining independence from the USSR in 1991, Ukraine possessed the world's third largest nuclear arsenal including almost 2000 strategic warheads, 170 intercontinental ballistic missiles (ICBMs), as also strategic bombers. In Dec 1994, the US, UK and Russia signed the 'Budapest Memorandum on Security Assurances' with Ukraine.

The agreement provided security assurance against use of force against Ukraine. It also promised to respect its sovereignty and existing borders. Based on this agreement, Ukraine surrendered all its nuclear weapons to Russia and signed the NPT. Today it faces loss of territory and attacks by Russia. Would it have happened if it had held onto its nuclear weapons? Agreements and promises mean nothing with passage of time.

The Kim Jong Un regime in North Korea is secure only because it possesses nuclear weapons. The nation may be isolated and amongst the world's most sanctioned, but no major power has ever attempted to push a regime change or destroy its nuclear stockpiles. It is reported to have sold nuclear weapon technology to nations including Pakistan but has yet to be acted against.

North Korea has over the years developed missiles capable of carrying nuclear warheads to Europe and the US imposing further caution. All that the west can do is impose sanctions and threats, which are meaningless against the authoritarian state.

Iran was attacked on 13th Jun because Israel felt threatened by it developing nuclear weapons. On the contrary, because it is a US ally, Israel's holding of nuclear weapons is acceptable. Tehran remains amongst the world's most sanctioned regimes. It was in talks with the US on its nuclear program, however Israel, with the backing of the US, decided to act unilaterally.

The US joined in the attack intending to destroy Iran's nuclear program. Rather than criticize Israel and US unilateral actions, the EU President commented that Iran must not be permitted to have nuclear weapons. A display of bias against specific nations.

The trigger for attacking Iran was the IAEA resolution in its board meeting on 12th Jun claiming Tehran was 'breaching its non-proliferation obligations.' The IAEA Director-General, Rafael Grossi, in a subsequent interview to al Jazeera on 19th Jun mentioned, 'Iran's alleged violations of its assurances had not led this agency to conclude that Tehran was building bombs.'

Both, Trump and Netanyahu, in their desperation to attack Iran ignored the statement by the US Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, who had mentioned, '(US intelligence) continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003.' Trump rebuked her on her statement.

Nations which are traditionally against western views and concepts will always remain at risk of being subjected to regime change, unless they possess reliable deterrent in the form of nuclear weapons. It is, in reality, a dominating west which encourages nuclear proliferation. But the world, as always, will remain silent.

Bolstering borders, providing cover

Major-General Ashok Kumar (retd)

The concept of having a Chief of Defence Staff (CDS) was announced by the Honourable Prime Minister from the ramparts of the Red Fort on August 15, 2019. This led to the historic appointment of General Bipin Rawat as the first CDS on December 31, 2019. Tragically, we lost him in a helicopter crash on December 8, 2021. Following a gap, the current CDS, General Anil Chauhan, was appointed on September 28, 2022. The creation of the post of CDS was aimed at achieving absolute synergy between the three services, which was demonstrated during Operation Sindoor.

The Chiefs of Staff Committee (COSC), comprising the three service chiefs, is the highest decision-coordinating authority within the military establishment. The senior- most service chief would serve as the Chairman of the COSC before the institution of CDS was established. Now, the CDS serves as the Permanent Chairman of the COSC, thus bringing in the requisite degree of jointness, integration, and optimal execution of all tasks. While the theatre-based structure of functioning under the CDS has yet to be operationalised, when Operation Sindoor commenced, the CDS led from the front, owing to his position as the Permanent Chairman of the COSC.

All three services made invaluable contributions to Operation Sindoor, and it would not be appropriate to compare one with another. Each service performed exactly according to their role based on the Pakistani threat. The armed forces operated with clockwork precision right from the morning of May 7, 2025 to May 10, forcing the Pakistani Director-General of Military Operations (DGMO) to approach his Indian counterpart, pleading for a ceasefire. The images that were released recently indicate that the CDS, along with the three service chiefs, monitored and guided the conduct of operations from the Army's Operations Room, signifying the special role played by the Indian Army. This role was enhanced as Pakistan chose to violate the ceasefire along the Line of Control (LOC), starting April 23. Pakistan fired high-calibre weapons, targeting schools and religious establishments, which led to the death of a number of innocent civilians. The Indian Army responded to these LOC violations comprehensively, inflicting substantial damage. In response to the Indian strikes on May 7, Pakistan launched close to 500 drones, activating the entire western front. This necessitated a robust response from the Army, which deployed a large number of air defence guns and missiles to neutralise this threat. To fully appreciate the Army's operational role, it is important to understand some background constructs, which are covered in the following paragraphs.

National context

The barbaric act of terrorism, sponsored and supported by the Pakistani government through its Army - particularly with the ISI playing a pivotal role since Pakistan adopted terrorism as part of its statecraft against India — was unleashed on tourists on April 22 at Pahalgam in Jammu and Kashmir, resulting in the killing of 26 men, who were selected based on their religion.

The Pakistani sponsors of this terrorist act appeared confident that they would succeed in widening the fault line between Hindus and Muslims. Moreover, they thought that they would also garner support from residents of the

Kashmir Valley as well as separatists. However, this assessment and attempt turned out to be their biggest strategic blunder. This heinous act united the entire country, cutting across regional, linguistic, religious, and all other identities, a phenomenon previously seen only during wartime. An unprecedented feeling of national unity emerged, with all Opposition parties, leaders from various regions and religious affiliations, and the entire population of the valley speaking in a common voice and echoing the declaration of the Government of India to target the terrorists, their infrastructures, and their supporters to send an unambiguous message to Pakistan as well as the world. The message to the world was communicated by the Prime Minister during his speech in Bihar, when he chose to speak in English to ensure its wider reach.

The Army was, therefore, confident of the support of the entire nation in the event of an escalation, as it would be able to mobilise the large number of troops currently deployed in counterinsurgency roles for warfighting. With the entire country united against terrorists, the rear lines of communication would also become secure. The absolute support allowed the Army to refrain from mobilisation for conventional operations unlike Pakistan, which not only beefed up its troop presence along the LOC but also mobilised its 12 Corps from Balochistan and North-West Frontier Province to the Indian borders. However, the Indian Army had a different plan to achieve its mission.

Securing success in each stage

There were times in warfighting when losing a battle was not considered a setback as long as one was winning the war. However, this philosophy underwent a change with the decline of long wars, as control over the termination of conflict was not even in the hands of the final victor. It, therefore, became necessary to maintain a winning profile at the end of each operational cycle so that even if the war ended abruptly, one could maintain the winning edge. In modern days, a new warfighting strategy was needed, and therefore, the Indian Army adopted an approach to be on the winning side at the end of every engagement. This is one of the biggest takeaways from Operation Sindoor, during which this approach was practised and proved to be successful. This is a new normal created by India for the world to emulate.

It is very important to understand this changed doctrine as it helps the victor to come out of a conflict by using a carefully planned exit strategy and being in full control of the escalation matrix. The absence of such a strategy results in a prolonged conflict, which is evident in the case of the Russia-Ukraine war as well as the Israel- Hamas conflict. Despite Russia and Israel being vastly superior to their respective opponents, both remain stuck in the battle of attrition. In contrast, India's winning strategy at the end of each day or round was the real mantra for achieving its national aim in the shortest timeframe.

Innovative thinking

The Indian Army practised and evolved multiple new concepts related to the innovative use of forces and resources during Operation Sindoor, all in close coordination with the other two services. These will become part of new doctrinal changes for future warfighting. The details are deliberately not being covered as Operation Sindoor is still continuing.

India began adopting and practising newer approaches in a mission mode following the Chinese transgressions in eastern Ladakh in April-May 2020. This tri-services effort gained momentum with the current CDS focusing on future warfighting and involving all ranks to enhance their preparedness. This proved useful during Operation Sindoor as the Army had skilled itself well in recent years, with a focus on technology adoption.

Army air defence

Besides the long-range vectors of various kinds unleashing an unprecedented degree of destruction in Pakistan, the Army's air defence

stands out as the most significant success of Operation Sindoor. The systems performed remarkably despite Pakistan launching a barrage of drone attacks along the entire western front, starting from Jammu and Kashmir and going up to Gujarat through the States of Punjab and Rajasthan. The air defence wall created by the Indian Army neutralised all incoming threats, achieving a 100% success rate, rarely achieved even by countries like Russia and Israel. Its success also played a crucial role in escalation management. Had this wall not functioned the way it did, the damage to our military and civil infrastructure would have resulted in a stronger retribution. Some of the key features are as follows:

• Tiered deployment: This covered the entire western front based on all types of resources that Pakistan could launch across the breadth, length, and altitudes of our country. A synergised deployment of Army air defence resources interspersed with the IAF resources was undertaken.

• Gap-free coverage: All kinds of surveillance resources - satellites, early warning radars, local warning radars, fire control radars, observers, and so on - were employed to ensure gap-free coverage. This resulted in early detection of targets, allowing requisite time to respond.

•Efficient control and reporting systems: This is the crucial link between target and weapon matching. There was seamless integration between the Integrated Air Command and Control System (IACCS) of the Air Force and the Akashteer system of the Army Air Defence. This ensured identification of targets after their detection, irrespective of the reporting source. This was followed by target-weapon matching and allocating the most efficient weapon for the intended target. This automated and seamless process ensured 100% neutralisation of all incoming targets.

• Efficient weapon systems as terminators: While the Air Force had its aircraft, S-400 missiles, and other air defence resources, the Army Air Defence had a plethora of guns and missiles each tailored to specific types of threats. Thus, in the end, they neutralised all incoming threats, including drones, UAVs, and missiles.

The Indian Army has set a "new normal" in warfighting during Operation Sindoor. With the Prime Minister's declaration that every act of terror will be treated as an act of war, the strategies tested and doctrines evolved will need to be further refined to ensure round-the-clock battle readiness. Capability building for a two-front war (Pakistan and China) will need to go beyond preparing for conflict in two distinct geographies as operations may ultimately be concentrated in a single geography, as seen during Operation Sindoor. Higher capability development is a must to remain future ready.

In addition to the real fight, India must work towards maintaining the current spirit of national unity. This action, along with the elimination of terror, will release our forces entirely for external warfighting. With the government declaring its aim to eliminate Maoists by March 2026, a similar focused strategy is needed for the elimination of both insurgency and terrorism. Additionally, India must evolve an apex organisation to advance national narratives both during peace and war so that the propaganda of our adversaries claiming victory despite decisive loss can be nipped in the bud.

New Details Emerge on India's Devastating Strike on Noor Khan Airbase!!

Fresh revelations have surfaced, unveiling the staggering extent of damage inflicted by the Indian Armed Forces on Pakistan's Noor Khan Airbase, solidifying India's reputation as a global military brilliance!

This wasn't merely a military operation,i t was a world-record-level precision strike that obliterated Pakistan's strategic core, crippling their air and nuclear capabilities with surgical precision.

As fresh details emerge,the world is reeling from these new insights because India redefines the art of modern warfare.

Here's the electrifying breakdown.

Noor Khan Airbase

A fortress engineered with 3-5 meter thick steel-reinforced concrete bunkers, buried 40-50 meters underground, and fortified with cutting-edge EMP (Electromagnetic Pulse) protection, nuclear-capable air filtration systems, and a Faraday Cage to block all electromagnetic interference, including microwaves and radio signals.

It was constructed with American expertise from General Electric and linked to US satellite communication systems, can you believe it, this was Pakistan's ultimate C4I (Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence) hub, a facility designed to survive even a nuclear strike.

Nur Khan is located just 4 km from Pakistan's GHQ via a secure, non-public road, this bunker was their strategic plans division's nerve center, housing cyber command, satellite communications (SATCOM), and potentially VIP bunkers.

The Indian strike was carried out after two years of meticulous preparation!!The Indian Air Force executed a strike of unparalleled precision, targeting a ventilation shaft, a mere 2x2 foot opening from 600 km away traveling at near-supersonic speeds (just below the speed of sound)!! WOW!!

This pinpoint accuracy, guided by India's indigenous NavIC satellite navigation system, demolished two mobile command trucks, a Level C secure bunker (accessible only to top-tier personnel), and potentially nuclear-capable Ra'ad cruise missile storage!! WOW!!

The strike's impact was so devastating that it flattened a 40x40 meter section of the facility, with satellite imagery revealing a massive thermal anomaly (2.6°C to 4.1°C hotter than surrounding areas) and a completely demolished structure!!

This was no ordinary attack!!! It was a masterclass in kinetic and cyber warfare, paralyzing Pakistan's ability to respond!!

The Global Impact, the strike's ripple effects have reverberated across the global defense landscape, showcasing India's technological and strategic brilliance!!

By severing Pakistan's American SATCOM links, India disrupted their real-time data links critical for operating F-16 fighters, AWACS (Airborne Warning and Control Systems), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) networks. IN SIMPLEST TERMS PAKISTAN IS COMPLETELY CRIPPLED WITHOUT AN AIR DEFENSE SYSTEM!

The thermal anomaly detected by the European Union's Copernicus Sentinel-2 satellites and corroborated by US Global Hawk thermal maps confirmed the destruction of critical infrastructure, including cryogenically regulated weapon storage and climate-

controlled data centers.

This wasn't just a physical strike, it was a cyber-kinetic combo that knocked Pakistan's cyber command offline, corrupted their encrypted control systems, and triggered an automatic data dump to backup sites in Sargodha and Masroor, which India may have also targeted.

The internet blackout in the area just before the strike suggests India's intelligence agencies executed a preemptive cyber operation, rendering Pakistan's military blind and deaf.

This operation exposed vulnerabilities in NATO-standard bunkers (similar in design to those in Turkey), forcing global powers to reassess their own defense architectures.

The strike's precision, achieved with a Circular Error Probable (CEP) of mere feet, sets a new benchmark for missile accuracy, rivaling and surpassing systems like the American Tomahawk or Israeli Delilah.

Defense analysts worldwide, from Jane's Review to The Defense Forum, are buzzing about India's ability to neutralize a nuclear-capable command center, signaling to adversaries that India can strike with impunity, anywhere, anytime!

This has not only humiliated Pakistan but also sent a chilling message to global powers! India's NavIC-guided arsenal and open-source intelligence (OSINT) capabilities are a force to be reckoned with, reshaping the geopolitics of warfare.

India's Message: Decapitation Lite Redefines Warfare ,This operation, dubbed "Decapitation Lite," wasn't about total annihilation but about surgically paralyzing Pakistan's ability to wage war. Unlike other global powers (yes, we're looking at Israel and the USA), who have struggled to effectively target C4I infrastructure (like Iran's), India executed a textbook operation that left Pakistan's secondary strike capability, their ability to retaliate after a first strike in ruins!!

The brilliance lies in its restraint! India didn't just destroy; it dismantled Pakistan's strategic confidence.

By targeting the ventilation shaft, India ensured maximum disruption with minimal collateral damage, showcasing a level of sophistication that blends kinetic precision with cyber dominance.

The NavIC system, India's answer to GPS, proved its mettle by guiding the missile to a target smaller than a drum, a feat that stunned analysts given the 600 km range and high-altitude flight path.

The strike also exposed Pakistan's over-reliance on American technology, as their F-16 data links and SATCOM systems went offline, leaving their air force "flying blind." The operation's success is a testament to India's two-year rehearsal, which included mock strikes and intelligence-gathering through OSINT and possibly human intelligence (HUMINT), as hinted by the mysterious disappearance of a source codenamed Falcon Striker 72 within 36 hours of leaking critical details.

This strike has silenced critics who doubted India's capabilities, proving that while others talk of controlling the skies, India owns the air.

Pakistan's dilemma is stark: they can't admit this catastrophic loss...imagine confessing that India obliterated their nuclear command center, leaving their generals helpless and their secure lines severed.

The world now sees India as a master of asymmetric warfare, capable of dismantling fortified targets with surgical precision while maintaining plausible deniability.

This operation, likened to a "bamboo stick beating wrapped in a blanket" (no visible scars, but unbearable pain), has left Pakistan reeling, unable to prove or retaliate!!

Let's salute our brave forces and intelligence operatives who made this historic feat possible!!

Let's celebrate India's triumph and send a message to the world ..Bharat is rising, unstoppable, and rewriting the rules of modern warfare!!

JAI HIND!!

(Received from a Veteran)

China, Pakistan and Bangladesh form trilateral bloc

Anish Kumar

A day ago, Bangladesh, China and Pakistan launched a trilateral cooperation mechanism to promote economic development and improve people's livelihoods.

In a meeting held in Kunming on June 19 in China, three sides emphasised that China-Bangladesh-Pakistan ties adhere to true multilateralism and open regionalism, not directed at any third party, according to the Chinese Ministry of Foreign Affairs.

Trilateral bloc, a concern for India

It is a well-known fact that China and Pakistan are all-weather friends but the joining of Bangladesh and forming a trilateral bloc is a cause of concern in Indian circles. About a year back, Dhaka used to be a good friend of Delhi since the country helped in their liberation from Pakistan. But things changed after the stepping down of the then Bangladesh prime minister Sheikh Hasina in August 2024.

Bangladesh is currently under the regime of an interim government headed by Nobel laureate Mohammad Yunus, appears more aligned with India's adversaries such as China and Pakistan.

Experts on the 'devil triangle'

Asianet Newsable English has spoken to a number of foreign and security affairs analysts to understand the developments taking place in India's neighbourhood.

Calling it the devil triangle with potential to challenge India's dominance in Bay of Bengal, Geostrategic and security experts Major General Sudhakar Jee said: "The triangle could choke Siliguri corridor and cut off northeast from the mainland of India and also sow seeds to balkanise India from both the continental borders and the IOR."

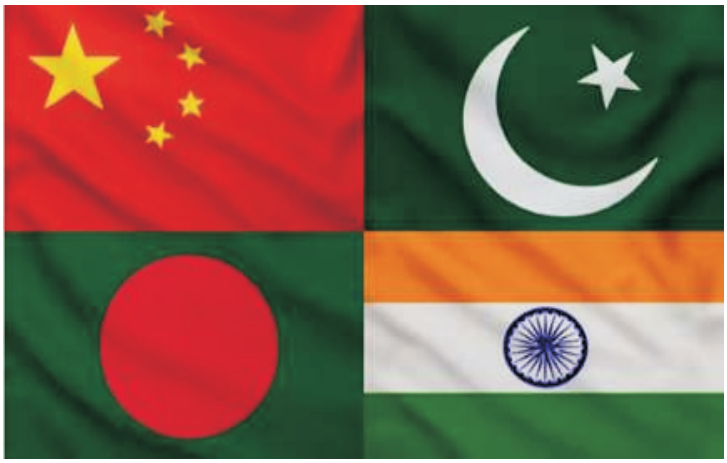

It will also present a two front threat permanently and strategise BRI (Border Road Initiative) to develop and secure access to warm waters in Bay of Bengal and Arabian Sea."

Sudhakar Jee is also of the view that Beijing, Dhaka and Islamabad would try for intersection of "strategic encirclement" and

"strategic triangle" to pressurise India to toe their demands.

Gautam Lahiri, an expert on Bangladesh affairs said: "It is disturbing news for India from a security point of view. The new dispensation is trying to become familiar with the old Pakistan and China. This triangle of Pakistan, Bangladesh, and China is yet to show its full impact."

"They have said they will concentrate on economic issues, trade issues, etc. But the point is – in Pakistan and POK – the Chinese have been building CPEC (China Pakistan Economic Corridor) which is a major security concern for India. I think India should be alarmed and should take appropriate measures so that India's security is not hampered," Lahiri said.

Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS) director general Major General Ashok Kumar (Retd) said: "After the change of regime in Bangladesh, Dhaka has bandwagoned China and Pakistan. It is on its way to becoming East Pakistan. Not only this, Bangladesh has also been moving in the lap of China."

"Now this three nation grouping appears to be getting stronger with each passing day. The alignment is primarily taking an anti-India shape."

"It is hoped that Bangladesh may come out of this grouping if fair elections are conducted and some sensible government is formed. India has to use its diplomatic ingenuity to ensure that this grouping doesn't become stronger," the CENJOWS DG added.

Former Bangladesh Army officer and diplomat Major General Shahidul Haq (Retd), who had also served as an ambassador to several countries, said: "These countries have already mentioned in their statements that it is not directed to any third country.

"Most of the Bangladeshis don't want any strategic or defence or military alignment with anybody. This was what everybody very strongly felt. I also read statements from all these three countries and found out that more economic and common social parameters are included in it," Shahidul Haq said.

Subhashish Banerjee, Founder, P3 Think Tank, said: "It is now crystal clear that China is trying to take control of the Asian economic corridor, and thus, creating space for the Belt and Road Initiative is nothing but a primary thought process. This cannot be endorsed as an act of a mature power. It looks more like a self-centric approach than a collaboration."

"Bangladesh and Pakistan's ruined economy has attracted obvious attention of the nations who are interested in establishing the sense of political control in the Asian market," Subhashish Banerjee said.

"But considering the fact that India leads the consumer market of the world, any overambitious draft endorsed to sideline or isolate India's interest is nothing but an attempt of building a castle out of cards. China must understand that when the entire world is trying to create chairs for India as a power, creating nuisance just for the sake of seeking control may attract huge international criticism because Pakistan as a territory is already a proven terror enthusiast and Bangladesh is already in the state of destabilisation," he added.

Operation Sindoor redraws China's outreach

In the aftermath of Operation Sindoor, India's military operation against terrorist infrastructures in Pakistan, China has been trying to consolidate its position in the South Asian region and it could be a reason that Beijing is bringing together two of India's immediate neighbours – Pakistan and Bangladesh under its fold. India and China had also engaged in border standoff in eastern Ladakh for around five years and the troops from both sides disengaged only last year in October.

Welfare

15 GOLDEN POINTS FOR DEFENCE PENSIONERS
रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 15 स्वर्णिम बिंदु
MOST IMPORTANT INFORMATION FOR ALL PENSIONERS
सभी पेंशनभोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना

1) Pension will be paid to the wife of a Pensioner only if her name and Date of Birth is mentioned in PPO and is matching with her name and Date of Birth in Bank account.

1) पेंशनभोगी की पत्नी को पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका नाम और जन्म तिथि पीपीओ में उल्लिखित हो और बैंक खाते में उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो।

2) If wife's Name and Date of Birth (DOB) in the PPO is matching with her name and Date of Birth in Bank account then there is no problem- The original PPO can be continued for wife also- There is no requirement of a separate PPO for the wife- She has to submit the death certificate of her husband in the bank along with her Aadhar Card] PAN card] etc- to get pension- In a normal course] it will get credited within one or two months.

2) अगर पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तिथि (डीओबी) उसके नाम और बैंक खाते में जन्म तिथि से मेल खा रही है तो कोई समस्या नहीं है। पत्नी के लिए भी मूल पीपीओ जारी रखा जा सकता है। पत्नी के लिए अलग पीपीओ की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंशन पाने के लिए उसे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा। सामान्य तौर पर, यह एक या दो महीने के भीतर क्रेडिट हो जाएगा।

3) The wife's Name and DOB have to match in following four documents:

(1) Pension Payment Order-

(ii) Pension Bank Account- (Joint Account)

(iii) Wife's Adhaar Card-

(iv) Wife's PAN Card

3) पत्नी का नाम और जन्मतिथि निम्नलिखित चार दस्तावेजों में मेल खाना है–

(i) पेंशन भुगतान आदेश।

(ii) पेंशन बैंक खाता। (संयुक्त खाता)

(iii) पत्नी का आधार कार्ड।

(iv) पत्नी का पैन कार्ड

4) If the wife's name is not mentioned in PPO, then she will not get pension immediately after death of Ex-Servicemen. In that case, She has to submit their marriage certificate, give notification in two National news papers, get an affidavit signed by a First class magistrate] etc and then send all the documents to Records through Sainik Welfare Office. Records will then scrutinize and send the documents to PCDA Allahabad. PCDA will issue Corrigendum PPO sanctioning the family pension- It will take at least one year for getting Corrigendum PPO. Thereafter, she has to go to bank and submit all documents to get her pension. The whole process will take atleast one year after submission of all the documents correctly.

4) अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। उस मामले में, उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा, दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना देनी होगी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा प्राप्त करना होगा, आदि और फिर सभी दस्तावेज सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड्स को भेजना होगा। इसके बाद अभिलेखों की जांच की जाएगी और पीसीडीए इलाहाबाद को दस्तावेज भेजे जाएंगे। पीसीडीए परिवार पेंशन को मंजूरी देते हुए शुद्धिपत्र पीपीओ (Corrigendum PPO) जारी करेगा। शुद्धिपत्र पीपीओ प्राप्त करने में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा।

इसके बाद, उसे बैंक जाना होगा और पेंशन पाने के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने के बाद पूरी प्रक्रिया में कम से कम एक साल लग जाएगा।

5) Wife may also face a problem in getting pension if her name and Date of birth is not matching properly with any of the above four documents.

5) पत्नी को पेंशन पाने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है यदि उसका नाम और जन्म तिथि उपरोक्त चार दस्तावेजों में से किसी के साथ ठीक से मेल नहीं खाती है।

6) So, what should an Ex-Serviceman do? An Ex-Serviceman has to take the following actions when he is alive. Otherwise, the wife may have tremendous problem in getting the pension after death of the Ex-Serviceman.

6) तो, एक भूतपूर्व सैनिक को क्या करना चाहिए? एक भूतपूर्व सैनिक को जीवित रहने पर निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। अन्यथा पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पेंशन पाने में पत्नी को भारी समस्या हो सकती है।

7) Ex-Serviceman should get the name and date of birth of his wife notified correctly in Pension Payment Order. It is called " Joint Notification of Pension".

7) भूतपूर्व सैनिक पेंशन भुगतान आदेश में अपनी पत्नी का नाम और जन्मतिथि सही–सही अधिसूचित करवा लें। इसे 'पेंशन की संयुक्त अधिसूचना' कहा जाता है।

8) Ex-Servicemen who have retired before 1986 should get joint notification of Pension on wife's name even though her name is mentioned in PPO. These are Government of India Orders. So, don't neglect and don't question. The forms are available in Sainik Welfare Office and please apply immediately. Otherwise, wife will not get pension after the death of Ex-Serviceman.

8) भूतपूर्व सैनिक जो 1986 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पत्नी के नाम पर पेंशन की संयुक्त अधिसूचना प्राप्त करनी चाहिए, भले ही उसका नाम पीपीओ में उल्लिखित हो। ये हैं भारत सरकार के आदेश। इसलिए, उपेक्षा न करें और सवाल न करें। फॉर्म सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध हैं और कृपया तुरंत आवेदन करें। अन्यथा भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी।

9) If the wife's name in PPO is not matching with the name in Bank account, Aadhar and PAN card, then Ex-Serviceman has to apply to Record Office through Sainik Welfare Office for change of name of wife in PPO. Some records ask for a Gazette while others may ask for an Affidavit signed by a First Class Judicial Magistrate. It will take at least six months for change of name of wife in PPO- So, take action immediately.

9) यदि पीपीओ में पत्नी का नाम बैंक खाते, आधार और पैन कार्ड में नाम से मेल नहीं खाता है, तो भूतपूर्व सैनिक को पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। कुछ रिकॉर्ड एक राजपत्र मांगते हैं जबकि अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा मांग सकते हैं। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम से कम छह महीने लगेंगे। इसलिए तुरंत कार्रवाई करें।

10) If the name of wife in Aadhar or PAN card is different, then get them corrected before applying for change of name in PPO- Please go to Aadhar centre or concerned Government office and apply. It will be rectified in two or three weeks. Thereafter, apply to Record Office through Sainik Welfare Office for change of name of wife in PPO. Change of name of wife in PPO will take at least 6 months- So] donot delay.

10) अगर आधार या पैन कार्ड में पत्नी का नाम अलग है तो पीपीओ में नाम बदलने के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें सही करवा लें। कृपया आधार केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करें। दो–तीन सप्ताह में इसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड

कार्यालय में आवेदन करें। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो, देर न करें।

11) If the pension Bank account is a Joint account, then the pension for wife will be credited to the same account after death of an eX-serviceman- She need not open another single account- Some Branch managers insist on opening another single account- Govt of India and RBI have already instructed Banks not to force a widow to open a separate Single Account on her name in the same branch and Bank if the pension account is a joint account and name of wife in Bank account and PPO are matching.

11) यदि पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता है, तो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन उसी खाते में जमा की जाएगी। उसे एक और एकल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शाखा प्रबंधक एक और एकल खाता खोलने पर जोर देते हैं। भारत सरकार और आरबीआई ने पहले ही बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि पेंशन खाता एक संयुक्त खाता है और बैंक खाते और पीपीओ में पत्नी का नाम मेल खाता है तो एक विधवा को उसके नाम पर एक ही शाखा में एक अलग एकल खाता खोलने के लिए मजबूर न करें।

12) However, if the Pension account is not a Joint account] then she has to open a separate single account in the same branch and it may take atleast 6 months or one year for the family pension to start- So] convert your pension account into a Joint account immediately with your wife.

12) हालांकि, यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता नहीं है, तो उसे उसी शाखा में एक अलग एकल खाता खोलना होगा और पारिवारिक पेंशन शुरू होने में कम से कम 6 महीने या एक वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए, अपने पेंशन खाते को तुरंत अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में बदल दें।

13) So, please take the following actions immediately to avoid difficulty to your wife:

a) Check your wife's name in PPO] Bank account] Aadhar Card and PAN Card- The name in all documents should be same- If not take action as eÛplained above.

b) Check your wife's date of birth in PPO] Bank account] Aadhar Card and PAN Card- It should be same in all documents- If not take action as eÛplained above.

c) Pension account should be a joint account with your wife. If not convert it into a joint account.

13) इसलिए, कृपया अपनी पत्नी को कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निम्नलिखित उपाय करेंरू

a) पीपीओ, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी का नाम जांचें। सभी दस्तावेजों में नाम समान होना चाहिए। यदि ऊपर बताए अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं।

b) पीपीओ, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी की जन्मतिथि की जांच करें। यह सभी दस्तावेजों में समान होना चाहिए। यदि ऊपर बताए अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं।

c) पेंशन खाता आपकी पत्नी के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए। यदि इसे संयुक्त खाते में परिवर्तित नहीं करते हैं।

14) Please Keep your Original & Corrigendum PPO (if issued) safe- It is the most important documents for getting family pension- Make two or three XeroÛ copies and keep it at different places.

14) कृपया अपना मूल (Original) और शुद्धिपत्र पीपीओ (Corrigendum PPO) (यदि जारी किया गया है) सुरक्षित रखें। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जेरोक्स की दो या तीन प्रतियां बनाकर अलग–अलग जगहों पर रख दें।

15) If you are getting pension through SPARSH] newly introduced defence pension system] then communicate SPARSH Usery & Password to your wife.

15) यदि आप स्पर्श, नई शुरू की गई रक्षा पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो अपनी पत्नी को स्पर्श उपयोगकर्ता और पासवर्ड के बारे में बता कर रखें या डायरी में लिखकर रखें।

गतिविधियां (Social Activities)

– जे. बी. एस. चौहान

जोधपुर (राजस्थान)– दिनांक 22 जून 2025 को गौरव सेनानी तिरंगा रैली तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संगोष्ठी एवं नवगठित इकाई, छोटीखाटू का गठन समारोह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस समारोह का आयोजन, जोधपुर प्रांत के वरिष्ठ उपाधक्ष कर्नल मदन सिंह जोधा की अगुवाई में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर प्रांत अध्यक्ष मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित थे। साथ ही अतिथियों की एक लंबी कतार थी जिसमें पूर्व जिला सैनिक कल्याण प्रभारी अधिकारी, वर्तमान में अधिकारी, तथा ECHS प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह, ग्रुप कैप्टन गणपत सिंह राठौड़, कर्नल राजेन्द्र सिंह, कर्नल दीप सिंह, कर्नल प्रताप सिंह, कर्नल दिलीप सिंह, कर्नल मनोहर सिंह, कर्नल मदन सिंह, कर्नल अनिरुद्ध सिंह, विंग कमांडर। एमपी बेनीवाल। विशेष अतिथि के रूप में सुश्री, ब्रह्माकुमारी आश्रम डीडवाना, संत श्री शंकर महाराज, बगीची छोटी खटू श्री गिरधारी राम जी, संघ प्रचारक नगौर, श्री जितेंद्र सिंह जोधा, विधायक, डीडवाना, श्री नरसिंह चरण, तहसीलदार छोटूखाटू, श्रीदेवी लाल बिश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक , छोटी खाटू, श्री अशोक भाई साहब, संघ प्रचारक छोटी खाटू, जोधपुर प्रान्त से पधारे फ्लाइंग ऑफीसर नारायण सिंह जोधा, प्रांत महासचिव, सीपीओ जबर सिंह राठौर संघठन सचिव कैप्टन भगवान सिंह भाटी, बावड़ी इकाई अध्यक्ष, हवलदार नरेंद्र कुमार चौधरी तथा भंवर सिंह राठौड़ के साथ छोटी इकाई के लगभग 75 गौरव सैनिकों ने भाग लिया। साथ ही 6 वीरांगनाएं भी उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ और समाप्ति राष्ट्रगान से हुई।

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)–दिनांक 25.6.2025 को जनपद बुलंदशहर के आरआर होटल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तहसील बुलंदशहर की मीटिंग आयोजित की गई इस मीटिंग का संचालन राम लखन के द्वारा किया गया आज की इस मीटिंग में 20 नए पूर्व सैनिक और पांच मातृशक्ति को संगठन की सदस्यता ग्रहण कर संगठन से जोड़ा गया साथ ही आने वाले समय में कारगिल विजय दिवस समारोह के संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं संगठन के विस्तार को गति देने संबंधित पहलुओं पर विचार विमर्श किया।

पुणे (महाराष्ट्र)–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पुणे महानगर की बैठक दिनांक 06 जुलाई को पुणे महानगर अध्यक्ष कर्नल नरेश गोयल जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में भाषण के समय मंच पर राष्ट्रीय संगठन सचिव मा. डॉ. जयप्रकाश शर्मा, एवम् प्रदेशाध्यक्ष एयर मार्शल प्रदीप जी बापट आसीन रहे। साथ ही बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया।इसी के साथ महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा महानगर कार्यकारिणी भी घोषित की गयी। राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष ने भी बैठक को संबोधित किया।

कानपुर (उत्तर प्रदेश)–13 जुलाई को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कानपुर ने मासिक बैठक का आयोजन किया जिसमें कारगिल विजय दिवस मनाने की योजना बनाई। मीटिंग से पहले सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने वृक्षारोपण किया।

इंदौर (मध्यप्रदेश)–आज दिनांक 13 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इंदौर इकाई एवं महाकौशल प्रांत के सदस्यों के साथ साथ सैन्य मातृशक्ति पदाधिकारियों की मासिक बैठक प्राणायम प्लस, एच आई जी ई 27 मे आयोजित की गई जिसमे बैठक में मालवा प्रांत के अध्यक्ष विंग कमांडर डी पी तिवारी जी, महासचिव जे एस अहिरवाल जी जिला इंदौर इकाई के अध्यक्ष कर्नल सुधीर ताम्हने जी, महासचिव फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस पी विश्वकर्मा जी, प्राणायाम प्लस के संचालक स्क्वाड्रन लीडर त्यागी जी और अन्य कार्यकरिणी पदाधिकारीगण एवं सैन्य मातृशक्ति पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कारगिल द्रास की यात्रा से वापस आने वाले सहभागियों ने अपने विचार साझा किए। आगामी मध्य प्रदेश प्रतिनिधि सभा बैठक (एजीएम) की एक दिवसीय बैठक जिला इंदौर, मालवा प्रांत में आयोजित करने का प्रस्ताव सार्जेंट रमेश पाण्डेय, राष्ट्रीय सचिव द्वारा सितंबर या अक्टूबर 2025 मे करने का रखा जिसे उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। स्वागत उद्बोधन जिला इंदौर इकाई के अध्यक्ष कर्नल साहब ने किया,मालवा प्रांत के अध्यक्ष विंग कमांडर तिवारी जी ने पूर्व सैनिको और उनके परिवार के

संबंध में जानकारी दिए। बैठक का संचालन जिला महासचिव फ्लाइंग लेफ्टिनेंट एस पी विश्वकर्मा जी ने किया और आभार प्रांतीय महासचिव सार्जेंट अहिरवाल ने व्यक्त किए। अंत मे सामूहिक राष्ट्रगान के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

रीवा (मध्यप्रदेश)–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा की बैठक 13 जुलाई को सुबह 11.00 बजे सैनिक विश्राम गृह रीवा मे राष्ट्रीय सचिव सार्जेंट रमेश पाण्डेय जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन अनिल कुमार सिंह ने किया और संचालन जिला महासचिव कैप्टन बी जी शर्मा जी ने किया। बैठक मे राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि 26 जुलाई को आगामी विजय दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेजर जनरल आर के गुप्ता जी, प्रांतीय अध्यक्ष मेजर जनरल निश्चय राउत जी जबलपुर और ब्रिगेडियर एस बी सिंह जी भोपाल के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। स्थानीय राजनीतिक नेता जैसे उपमुख्यमंत्री जी, रीवा सांसद जी व अन्य को भी आमंत्रित करेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की अत्यावश्यक बैठक 25 जून 2025 को श्रीमती मंजू सिंह, अध्यक्षा मात्रि शक्ति, अवध प्रांत के आवास, ब्रंदावन योजना लखनऊ में आयोजित हूई। इस बैठक में कर्नल आर पी सिंह, ले. कर्नल बीएस तोमर, अध्यक्ष, अवध प्रांत, मेजर आनंद टंडन, प्रदेश संगठन सचिव, सूबे मेजर बीएल वर्मा, उपाध्यक्ष अवध प्रांत, सूबे मेजर जेबीएस चौहान महासचिव, अवध प्रांत, सूबे कामता सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष लखनऊ महानगर, श्रीमती मंजू सिंहजी एवं श्रीमती पूनम सिंह, अध्यक्ष मात्रिशक्ति लखनऊ उपस्थित रहीं। दयाल रेजीडेंसी, अयोध्या रोड लखनऊ से चार पूर्व सैनिकों कैप्टन शत्रुघ्न सिंह, वीर चक्र सम्मान प्राप्त, सूबेदार सर्व जीत सिंह, सूबेदार मणि कुमार तिवारी और सूबेदार पवन कुमार सिंह ने भी इस बैठक में भाग लिया। परिचय विवरण में ही कैप्टन शत्रुघ्न सिंह ने कारगिल युद्ध में युद्ध के समय की अपनी वीरता भरी सच्ची कहानी सुनाई जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र सम्मान प्रदान किया गया। तदोपरांत अध्यक्ष तोमर साहब और मात्रिशक्ति अध्यक्षा ने अंगवस्त्र एवं संगठन की टोपी पहना कर उन्हें सम्मानित किया। और सभी पूर्व सैनिकों को संगठन में शामिल किया गया। इस बैठक का आयोजन कुछ दिनों पूर्व रायबरेली रोड पर एक सब इंस्पेक्टर द्वारा सेना में सेवा दे रहे लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ अभद्रता/मारपीट करने के विरोध में थी। सभी पूर्व सैनिकों ने इस घटना पर अपना रोष व्यक्त किया।

हरदोई (उत्तर प्रदेश)–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरदोई द्वारा सर्वदमन सिंह फौजी के आवास पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राजेश जी विभाग संपर्क प्रमुख उन्नाव एवं विनय जी नगर कारवां हरदोई एवं राजवर्धन जी जिला सह शारीरिक प्रशिक्षण प्रमुख तथा मीडिया प्रकोष्ठ के सभी मित्र एवं संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए, संगठन के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह फौजी ने सभी का स्वागत कर परिचय कराया, तत्पश्चात राजेश जी ने संघ से परिचय कराते हुए अपने कर्तव्यों एवं देश हित, भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं संस्कारों के बारे में सभी को बताया।

कोटद्वार उत्तराखंड–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोटद्वार द्वारा 1992 से कोटद्वार में केन्द्रीय विद्यालय की मांग को इस समय उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी जो मेजर जनरल भुवन चन्द साहब की वेटी सभी पूर्व सैनिकों के हित में यह तोहफा दिया।

जबलपुर (मध्यप्रदेश)– अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जबलपुर इकाई द्वारा प्रदत्त प्रेरणा स्वरूप, जबलपुर नगर में वीर नारियों और सम्मान पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक गरिमामय नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन, महाकौशल शहीद स्मारक ट्रस्ट, गुंजन कला सदन, पी.एम.जी. पाथेय संस्था एवं सुप्रभातम् क्लब आदि नगर के प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जबलपुर की वीर नारियों, पराक्रम पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों, तथा समर्पित सैन्य संगठन सदस्यों को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जबलपुर एवं आयोजकों ने विश्वास जताया कि यह परंपरा अन्य नगरों में भी एक मॉडल के रूप में उभरेगी और समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देगी।